वर्ष 12 • अंक 247 • 14 पृष्ठ • मूल्य 5 रुपये

बुधवार 4 दिसंबर 2019

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

पृष्ठ 6

महाराष्ट्र में चीनी उत्पादन घटा

नवीन जिंदल पृष्ठ 2

ओडिशा लौह अयस्क पर गतिरोध जारी

डॉलर रु. 71.70 (अपरिवर्तित) | यूरो रु. 79.40 ▲ 50 पैसे | सोना (10ग्राम) रु 38111 ▲ 284 रुपये | सेंसेक्स 40675.40 ▼ 126.70 | निफ्टी 11994.20 ▼ 54.00 | निफ्टी फ्यूचर्स 12046.50 ▲ 52.30 | ब्रेंट क्रूड 60.60 डॉलर ▼ 0.20 डॉलर

एक नज़र

जेपी इन्फ्रा के लिए जमा कराई अंतिम बोली

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनबीसीसी लिमिटेड और मुंबई की सुरक्षा रियल्टी ने दिवालिया हो चुकी रियल्टी क्षेत्र की कंपनी जेपी इन्फ्राटेक के अधिग्रहण के लिए सोमवार को अंतिम बोलियां जमा कराईं। ऋणदाताओं की समिति ने उन्हें संशोधित बोली के साथ अंतिम पेशकश 3 दिसंबर तक देने को कहा था। हालांकि, दोनों कंपनियों की ओर से की गई अंतिम पेशकश के ब्योरे के बारे में तत्काल जानकारी नहीं मिल पाई है। इससे पहले सूत्रों ने कहा था कि दोनों कंपनियां अपनी पेशकश को और आकर्षक बना सकती हैं।

बीपीसीएल बिक्री पर एक रुपये में सलाह देगी डेलॉयट

देश के सबसे बड़े रणनीतिक विनिवेश में बिक्री साझेदार डेलॉयट महज एक रुपये ले रही है। डेलॉयट टच तोमात्सु इंडिया ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की बिक्री के लिए एक रुपये की पेशकश की है। इस बिक्री से सरकार को 70 से 80 हजार करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक एसबीआई कैपिटल्स ने 15 से 17 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी। इस बारे में डेलॉयट और एसबीआई कैपिटल्स ने ईमेल सवालों का जवाब नहीं दिया। पृष्ठ 4

सरकारी बैंकों ने बांटा 4.9 लाख करोड़ रुपये का कर्ज

वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने त्योहारों के दौरान अक्टूबर-नवंबर में 4.91 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड कर्ज बांटे। खपत बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सितंबर में बैंकों से गाहकों तक पहुंचने और जरूरी मानकों का पालन करते हुए जरूरतमंदों को कर्ज देने को कहा था। इसके बाद देश के 374 जिलों में कर्ज मेला आयोजित किया गया। इसमें एमएसएमई, एनबीएफसी, खुदरा तथा कृषि क्षेत्र के कर्जदारों पर विशेष जोर दिया गया।

चिदंबरम की जमानत याचिका पर फैसला आज

आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर उच्चतम न्यायालय बुधवार को अपना फैसला सुनाएगा। चिदंबरम ने उनकी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के 15 नवंबर के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। इस पर सुनवाई 28 नवंबर को पूरी हो चुकी थी और न्यायालय ने कहा था कि फैसला बाद में सुनाया जाएगा। पूर्व वित्त मंत्री इस समय 11 दिसंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में हैं।

आज का सवाल

क्या ई-फार्मेसी पर सरकार को जल्द बनाने चाहिए नियम

www.bshindi.com **पर राय भेजें।**
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या एनएसडीएल के कदम से कार्वी के ऋणदाताओं की बढ़ेगी मुश्किल? हां **77.78%** नहीं **22.22%**

जनवरी से मारुति की कारें महंगी

बीएस-6 से लागत बढ़ने और मुनाफे पर दबाव से अन्य कंपनियां भी बढ़ा सकती हैं दाम

शैली सेठ मोहिले और अरिदम मजूमदार
मुंबई/नई दिल्ली, 3 दिसंबर

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सूजुकी इंडिया लिमिटेड ने कच्चे माल की बढ़ती लागत के मद्देनजर आज अपने सभी मॉडलों की कीमत बढ़ाने की घोषणा की। बढ़ी कीमतें अगले साल जनवरी से प्रभावी होंगी। उद्योग के जानकारों और शीर्ष ऑटो डीलरों का कहना है कि बीएस-चार से बीएस-छह मानक में जाने की लागत के कारण बाकी सभी प्रमुख वाहन कंपनियां भी कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती हैं।

मारुति सूजुकी ने एक नियामकीय जानकारी में कहा कि कच्चे माल की लागत में बढ़ोतरी के कारण कंपनी के वाहनों की कीमत पर असर पड़ा है। इसलिए इस अतिरिक्त लागत का कुछ बोझ ग्राहकों पर डालना अपरिहार्य हो गया है। यही वजह है कि विभिन्न मॉडलों की कीमत बढ़ाई जा रही है।

देश के आठ प्रमुख बुनियादी उद्योगों के सूचकांक में अक्टूबर में 5.8 फीसदी की गिरावट आई। इनमें से इस्पात उद्योग में अक्टूबर में 1.6 फीसदी की गिरावट आई थी जबकि सितंबर में यह 1.5 फीसदी गिरा था।

1 जनवरी से कंपनी बढ़ाएगी दाम

- मारुति ने उतारे आठ बीएस-6 वाहन
- बीएस-6 की वजह से पेट्रोल कारों की लागत 15 से 20 हजार रुपये बढ़ी
- डीजल वाहनों के दाम में 50 से 70 हजार रुपये का हो सकता है इजाफा
- भारी छूट करी वजह से कंपनियों के मुनाफे पर पहले से ही है दबाव
- मारुति की प्रवर्तक कंपनी सुजूकी ने मुनाफे में कमी की चेतावनी दी

महिन्द्रा ऐंड महिन्द्रा के एक प्रवक्ता ने कहा कि उनकी कंपनी जनवरी की शुरुआत में कीमतें बढ़ाने पर विचार कर रही है। लेकिन इस बारे में अंतिम फैसला इस महीने के अंत में लिया जाएगा। जेएस 4व्हील मोटर प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं संस्थापक निकुंज सांघी ने कहा कि सभी कार कंपनियों के लिए कीमतें बढ़ाना जरूरी हो गया है क्योंकि बीएस-4 से बीएस-6 मानक में जाने से उनकी लागत बढ़ गई है। साथ ही बढ़ती छूट से उनका मुनाफा भी प्रभावित हो रहा है।

होंडा कार्स इंडिया में वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक (विपणन एवं बिक्री) राजेश गोयल ने कहा, 'कंपनी की जनवरी से कीमतें बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। आने वाले समय में जैसे-जैसे बीएस-6 संस्करण वाले कारें लाएंगे वैसे ही संबंधित दरें लागू हो जाएंगी।' टोयोटा किर्लोस्कर मोटर में उप प्रबंध निदेशक एन राजा ने कहा, 'कंपनी दो बातों का मूल्यांकन कर जनवरी 2020 से कीमतें बढ़ाने पर निर्णय लेगी। सबसे पहले हम पिछले छह महीनों के खर्च का मूल्यांकन करेंगे और उसके बाद बीएस-4 से बीएस-6 व्यवस्था में आने से जुड़े पहलुओं को ध्यान में रखेंगे।' राजा ने कहा कि कीमतें कितनी बढ़ेंगी इस बारे में फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन दिसंबर अंत तक कोई निर्णय जरूर लिया जाएगा।

सांघी ने स्पष्ट किया कि जिन कंपनियों का जोर डीजल वाहनों पर अधिक है, वे कीमतों में ज्यादा इजाफा करेंगी, जबकि पेट्रोल से चलने वाले वाहनों की कीमतें अपेक्षाकृत कम बढ़ेंगी। इस बीच, ज्यादातर कंपनियां अब भी यात्री वाहनों पर छूट दे रही हैं और दीवाली के मुकाबले यह थोड़ा ही कम है। मारुति सुजूकी में मुख्य वित्तीय अधिकारी अजय सेठ ने कहा, 'वित्त वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही में प्रति वाहन औसतन 25,761 रुपये की छूट दी गई। वित्त वर्ष 2019 की दूसरी तिमाही में यह आंकड़ा 18,758 रुपये प्रति वाहन था।' हालांकि वाहन उद्योग के सूत्रों का कहना है कि आर्थिक सुस्ती के मद्देनजर कंपनियां एकबारगी कीमतें बढ़ाने से परहेज करेंगी और विभिन्न चरणों में ऐसा कर सकती हैं। टाटा मोटर्स और हुंडई मोटर इंडिया के प्रवक्ताओं ने कहा कि उनकी कंपनियों ने कीमतें बढ़ाने पर कोई निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

ऑनलाइन दवा की बिक्री पर गिरेगी गाज!

सोहिनी दास
मुंबई, 3 दिसंबर

भारतीय औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) ने बिना लाइसेंस के परिचालन कर रहे ऑनलाइन दवा विक्रेताओं पर सख्ती दिखाई है। इसने 2 दिसंबर को भेजे अपने निर्देश में राज्य के दवा नियामकों से दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार जरूरी कार्रवाई करने को कहा है। अदालत ने पिछले साल दिसंबर में बिना लाइसेंस दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगा दी थी। किसी भी ऑनलाइन दवा विक्रेताओं को इस तरह का लाइसेंस जारी नहीं किया गया है क्योंकि फिलहाल इस क्षेत्र के विनियमन के लिए समग्र नियम नहीं हैं।

ई-फार्मेसी कंपनियां मार्केटप्लेस मॉडल के तहत काम कर रही हैं और लाइसेंसी दवा विक्रेताओं के साथ साझेदारी में चिकित्सक की पर्ची या प्राप्त ऑर्डर के आधार पर दवा की आपूर्ति करती है। सरकार से जुड़े सूत्रों का दावा है कि अगर मौजूदा मॉडल को अनुमति दी जाती है तो फिर इस क्षेत्र के नियमन के लिए नियम बनाने की क्या जरूरत है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, 'ऑनलाइन फार्मेसी के विनियमन के लिए नियमों का मसौदा पिछले साल जारी किया गया था। हालांकि अभी इसे अधिसूचित नहीं किया गया है। ऐसे में जब तक इसे अधिसूचित नहीं किया जाता है, तब तक ई-फार्मेसी मॉडल को परिचालन की अनुमति नहीं दी जा सकती है।' हाल ही में मंत्रिसमूह ने ई-फार्मेसी के लिए नियमन पर चर्चा की खातिर बैठक की थी।

(शेष पृष्ठ 4 पर)

बनेंगे नियम

- डीसीजीआई ने राज्य नियामकों से अदालत के आदेश के मुताबिक ऑनलाइन दवा बिक्री पर रोक लगाने को कहा
- ई-फार्मेसी कंपनियां कर रहीं औपचारिक अधिसूचना का इंतजार
- अधिसूचना को अदालत में दे सकती हैं चुनौती

सीएजी: 1,701 करोड़ की राजस्व हानि

बीएस संवाददाता
नई दिल्ली, 3 दिसंबर

- दिल्ली सरकार के विभागों ने 390 करोड़ रुपये की कमियों को माना
- वैट प्रणाली में निर्धारण में देरी के कारण राजस्व हानि

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट में दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में करीब 1,701 करोड़ रुपये की गड़बड़ियां पाई गई हैं। दिल्ली विधानसभा में 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए दिल्ली सरकार से संबंधित सीएजी के राजस्व एवं सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पर वर्ष 2019 के लेखापरीक्षा रिपोर्ट-2 प्रस्तुत किया गया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2017-18 के दौरान व्यापार एवं कर, राज्य उत्पाद शुल्क, परिवहन तथा राजस्व विभाग की 70 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच की गई। जिनमें 500 मामलों में शामिल 1,701.14 करोड़ रुपये का कम निर्धारण/राजस्व की हानि तथा अन्य अनियमितताओं का पता चला। संबंधित विभागों ने 390.39 करोड़ रुपये की राशि कमियों को स्वीकार किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि विभाग द्वारा खामियों की ओर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। रिपोर्ट में इनपुट टैक्स क्रेडिट, वैट में आपत्ति एवं अपील के मामले, राजस्व की गैर प्राप्ति, मांग के अनुरूप वसूली नहीं होने और ब्याज मद से संबंधित 705.58 करोड़ के वित्तीय मामलों का जिक्र है। रिपोर्ट के अनुसार करदाताओं द्वारा लंबित जीएसटी रिटर्न शीघ्रता से दाखिल कराने के लिए विभाग को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। 31 मार्च, 2015 को लंबित 31,726 मामले थे, जिनकी संख्या बढ़कर 31 मार्च, 2017 को 40,120 हो गई। इस दौरान इन मामलों के अनिर्णय की मांग राशि 4,944 करोड़ से बढ़कर 10,194 करोड़ रुपये हो गई। कारोबारियों द्वारा अपील के मामलों में कमी की प्रवृत्ति देखी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आपत्ति सुनवाई प्राधिकरण और अपील न्यायाधिकरण द्वारा विभाग के पक्ष में निर्णीत किये गये आपत्ति और अपील के मामलों पर सक्षम प्राधिकारियों द्वारा आगे कोई कार्रवाई नहीं करने के परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व की वसूली नहीं हो पाई।

दिल्ली कौशल व उद्यमिता विश्वविद्यालय को मंजूरी

दिल्ली विधानसभा ने आज राजधानी में कौशल व उद्यमिता विश्वविद्यालय खोलने को मंजूरी दे दी। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि प्रस्तावित विश्वविद्यालय में डिप्लोमा से लेकर रिसर्च तक की पढ़ाई होगी और पाठ्यक्रम की अवधि 6 माह से 2 वर्ष तक होगी। विश्वविद्यालय में 85 प्रतिशत सीटें दिल्ली के छात्रों के लिए होंगी। विश्वविद्यालय में छात्रों को नौकरी के हिसाब से तैयार करने के लिए उद्योग संगठन और उद्योगों से गठजोड़ किया जाएगा।

सरकार ने घटाई प्याज की भंडारण सीमा

प्याज की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार ने जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए खुदरा और थोक कारोबारियों के लिए प्याज स्टॉक सीमा घटा दी है। खुदरा कारोबारी 5 टन तक और थोक व्यापारी 25 टन तक ही प्याज का भंडारण कर सकते हैं। इस बीच, सूखे प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने पर भी विचार किया जा रहा है। वाणिज्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि प्याज संकट से निपटने के लिए बनाए गए मंत्रिसमूह के समक्ष सोमवार को यह प्रस्ताव रखा गया। भारत ने पिछले साल 10.2 करोड़ डॉलर का सूखा प्याज निर्यात किया था। *बीएस*

निर्माण में सुस्ती, अर्थव्यवस्था को चपत

हजारों अधबने फ्लैटों से खरीदारों, स्थानीय वेंडरों और प्रवासी मजदूरों की उम्मीदें धराशायी हो गई हैं

अर्णव दत्ता
नई दिल्ली, 3 दिसंबर

दिल्ली-एनसीआर में हैं 2 लाख से अधिक अधबने मकान

प्रमुख इलाके	अधबने फ्लैट की संख्या	अनुमानित कीमत (करोड़ रुपये में)
ग्रेटर नोएडा	100,000	43,600
नोएडा	42,500	36,700
गाजियाबाद	23,000	9,400

नवंबर की दोपहरी में रविंदर सिंह ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 16बी में आरजी लक्जरी होम्स के निर्माण स्थल की चहारदीवारी के बाहर बैठे अपने दो साथियों के साथ बातें कर रहे हैं। उन्होंने अपनी राइफल एक पेड़ पर टिका रखी है। 51 साल के सिंह सिक्योरिटी गार्ड हैं। वह और उनके साथी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उन्हें तीन महीने से वेतन नहीं मिला है। आरजी लक्जरी होम्स के निर्माण स्थल पर कभी जोरशोर से काम चलता था लेकिन छह महीने से निर्माण कार्य बंद पड़ा है। यह परियोजना राष्ट्रीय कंपनी कानून पंचाट में फंसी है। परियोजना में फ्लैट खरीदने वाले 1,600 खरीदारों ने शिकायत की थी कि नौ साल इंतजार करने के बाद भी उन्हें फ्लैट नहीं मिले हैं।

नरमी का असर

कभी इस साइट ऑफिस पर 30 अधिकारी तैनात थे लेकिन अब इसे रियल एस्टेट नियामक एवं विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने सील कर दिया है। सिंह अपने परिवार को कोई पैसा नहीं भेज पा रहे हैं। उनकी पूरी उम्मीद आरजी ग्रुप के अधिकारियों के इस वादे पर टिकी है कि दिसंबर में उन्हें पूरा भुगतान कर दिया जाएगा। उनके दोस्त भी सिक्योरिटी गार्ड हैं और उन्हें भी हर महीने 15,000 रुपये वेतन मिलता था। लेकिन उन्हें ज्यादा उम्मीद नहीं है। वे उस सिक्योरिटी एजेंसी को कॉल कर-करके थक गए हैं जिन्होंने उन्हें नौकरी पर रखा था। वहां कोई भी उनका फोन नहीं उठा रहा है और उन्हें संदेह है कि एजेंसी भी डेवलपर के साथ मिली हुई है। इस परियोजना के लिए 2010 से बुकिंग शुरू हुई थी और अभी तक खरीदारों को एक फ्लैट भी नहीं दिया गया है। इन फ्लैटों की कीमत 40 से 60 लाख रुपये के बीच थी और बहुमंजिला अपार्टमेंटों को मध्य आय वर्ग के परिवारों को लक्जरी होम बताकर बेचा गया था। लक्जरी तो छोड़िए, यहां एक भी ऐसा अपार्टमेंट खोजना मुश्किल है जिसका काम पूरा हुआ है। करीब पांच साल पहले यहां 700 मजदूर काम करते थे। निर्माण सामग्री से लदे ट्रकों को आना जाना लगा रहता था लेकिन अब यह जगह वीरान पड़ी है।

आरजी लक्जरी होम्स दिल्ली-एनसीआर की उन सैकड़ों परियोजनाओं में से एक है जिनका काम रुका हुआ है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था संकट में है। करीब एक किमी दूर आम्रपाली ड्रीम वैली का भी यही हाल है। अदालत के आदेश पर इसके प्रवर्तक जेल में हैं। इस टाउनशिप में कंक्रीट का ढांचा खड़ा है और मवेशियों का अड्डा है। यहां एक नोटिस चस्पा है कि यह प्रोजेक्ट उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है। नोएडा एक्सटेंशन और ग्रेटर नोएडा में आपको ऐसी कई परियोजनाएं दिख जाएंगी। इनमें से अधिकांश की शुरुआत 2010 से 2014 के बीच की गई थी जब रियल एस्टेट की कीमतें आसमान छू रही थीं। वर्ष 2015 में करीब 30 हजार फ्लैट लॉन्च किए गए थे लेकिन जुलाई-सितंबर 2019 तिमाही में एक भी नई परियोजना शुरू नहीं हुई।

(शेष पृष्ठ 14 पर)

खबरों में रहे स्टॉक

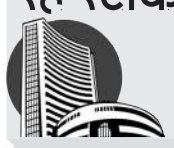

येस बैंक

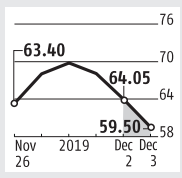

एफपीआई ने थोक सौदे के तहत बेचे 3.5 करोड़ शेयर

₹ 64.05 पिछला बंद भाव
₹ 59.50 आज का बंद भाव
▼ 7.10 %

आरबीएल बैंक

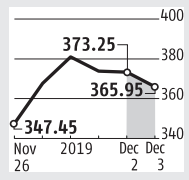

पात्र संस्थागत निवेश के लिए आधार मूल्य 352.57 रुपये तय

₹ 373.25 पिछला बंद भाव
₹ 365.95 आज का बंद भाव
▼ 1.96 %

प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स

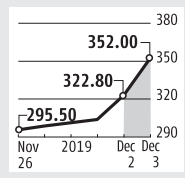

किराये वाली परिसंपत्तियों से प्रतिफल बढ़ने की उम्मीद

₹ 322.80 पिछला बंद भाव
₹ 352.00 आज का बंद भाव
▲ 9.05 %

ज्योति लैब्स

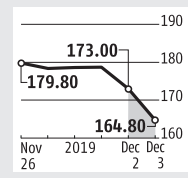

एफएमसीजी सूचकांक में सबसे अधिक गिरने वाला शेयर

₹ 173.00 पिछला बंद भाव
₹ 164.80 आज का बंद भाव
▼ 4.74 %

यूनाइटेड स्पिरिट्स

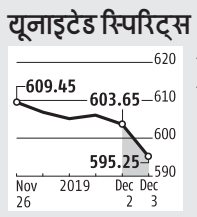

पायनियर डिस्टिलरीज के विलय की मंजूरी

₹ 603.65 पिछला बंद भाव
₹ 595.25 आज का बंद भाव
▼ 1.39 %

संक्षेप में

थॉमस कुक ब्रांड भारत में मौजूद रहेगा

थॉमस कुक इंडिया ने 14 करोड़ रुपये में अपने पूर्व प्रवर्तकों से इस यात्रा कंपनी के ब्रांड अधिकार हासिल किए हैं। कंपनी के चेयरमैन माधवन मेनन ने आज कहा कि अधिग्रहण के बाद भारत में थॉमस कुक का नाम नहीं बदलेगा और वह कारोबार को सुदृढ़ करने और नई प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करेगी। थॉमस कुक इंडिया अपने ब्रांड नाम के साथ 1881 से ही कारोबार कर रही है लेकिन पिछले कुछ वर्षों के दौरान उसके स्वामित्व में बदलाव देखा गया है। साल 1012 में जब फेयरफैक्स ने भारत, मॉरिशस और श्रीलंका में थॉमस कुक के कारोबार का अधिग्रहण किया था तो उसने सालाना 2 करोड़ रुपये के लाइसेंस शुल्क के भुगतान पर ब्रांड संबंधी अधिकारों को 2024 तक अपने पास बरकरार रखा था। *बीएस*

उज्जीवन के आईपीओ को 4.86 गुना अभिदान

उज्जीवन स्मॉल फाइनैंस बैंक के आईपीओ को मंगलवार को दूसरे दिन तक 4.86 गुना अभिदान मिला है। नैशनल स्टॉक एक्सचेंज के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 750 करोड़ रुपये के आईपीओ के तहत कुल 12,39,58,333 शेयरों की पेशकश की गई है। इस पर 60,29,84,400 शेयरों के लिए बोलियां मिली हैं। पक्यूआईबी खंड को 85 फीसदी अभिदान मिला है। गैर संस्थागत खंड को 2.46 गुना और खुदरा व्यक्तिगत निवेशक खंड को 23.85 गुना अभिदान प्राप्त हुआ। *भाषा*

ओडिशा लौह अयस्क पर गतिरोध जारी

सर्वोच्च न्यायालय ने टाली सुनवाई, जेएसपीएल का शेयर 12 फीसदी लुढ़का

अदिति दिवेकर
मुंबई, 3 दिसंबर

सारदा खदान मामला

- फैसला जेएसपीएल के खिलाफ रहने से प्रभावित नहीं होगा उसका परिचालन
- लेनदार चाहते हैं कि जिंदल स्टील को मिलना चाहिए लौह अयस्क
- जिंदल स्टील का खदान पर नियंत्रण हासिल करने पर जोर नहीं
- खदान परिसर में पड़े लौह अयस्क का खनन 18 से 21 महीने के दौरान हुआ

सर्वोच्च न्यायालय ने सारदा लौह खदान मामले में सुनवाई को फिलहाल टाल दिया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार किए जाने की खबरों के बीच जिंदल स्टील ऐंड पावर (जेएसपीएल) का शेयर आज दिन भर के कारोबार के दौरान 12 फीसदी लुढ़क गया।

जेएसपीएल के प्रबंध निदेशक वीआर शर्मा ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा, 'माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सारदा मामले में आज कोई फैसला नहीं सुनाया। उसने मामले की सुनवाई को 17 जनवरी के लिए टाल दिया है। टालने का मतलब इनकार करना नहीं होता।' बंबई स्टॉक एक्सचेंज पर जेएसपीएल का शेयर आज 6 फीसदी की गिरावट के साथ 150 रुपये पर बंद हुआ।

एडलवाइस सिक्योरिटीज ने आज एक ताजा नोट में कहा, 'अंतिम परिणाम आने में देरी से हम इनकार नहीं कर सकते क्योंकि इस फैसले में थोड़ा और समय लगेगा। हालांकि इस शेयर की प्रतिक्रिया (12 फीसदी की गिरावट) काफी चौंकाने दिख रही है।'

कंपनी के प्रबंधन ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति ने सारदा खदान स्थल पर पड़े लौह अयस्क पर जेएसपीएल का अधिकार साबित किया है।

शर्मा ने कहा, 'सारदा खदान परिसर में पड़े अयस्क का इस्तेमाल उपयोगकर्ता (जेएसपीएल) द्वारा अवश्य किया जाना चाहिए क्योंकि कंपनी सरकार को शुल्क के साथ-साथ रॉयल्टी का भी भुगतान पहले ही कर चुकी है। अब हम अंतिम फैसले का इंतजार कर रहे हैं जो अगले महीने आने की उम्मीद है।'

लौह अयस्क के लिए रॉयल्टी के भुगतान को लेकर ओडिशा सरकार और जेएसपीएल के बीच विवाद करीब 5 साल पुराना है। खदान परिसर में पड़े 1.2 करोड़ टन लौह अयस्क फाइन्स की कीमत करीब 2,000 करोड़ रुपये है।

एडलवाइस सिक्योरिटीज के विश्लेषकों ने कहा कि यह खदान फिलहाल परिचालन में नहीं है। फैसला पक्ष में आने पर कंपनी को अपने पैलेट संयंत्र के लिए लौह अयस्क की आपूर्ति सुनिश्चित होगी जिसके लिए वह फिलहाल खुले बाजार से खरीदारी कर रही है। यदि फैसला कंपनी के पक्ष में नहीं आया तो कंपनी के परिचालन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

प्रबंधन ने कहा कि सारदा खदानों के लिए पर्यावरण मंजूरियां संबंधी समस्याओं के कारण परिचालन बंद करने के आदेश से पहले 18 से 21 महीनों की अवधि में 1.2 करोड़ टन लौह अयस्क का खनन किया गया था। लेनदार भी जेएसपीएल के पक्ष में हैं और वे चाहते हैं कि कंपनी को वह लौह अयस्क मिलना चाहिए क्योंकि इससे उसे ऋण चुकाने में मदद मिलेगी।

ओडिशा के अंगुल में जेएसपीएल का 60 लाख टन क्षमता का इस्पात संयंत्र है। जबकि 90 लाख टन क्षमता का पैलेट संयंत्र बार्बिल में और टेंसा में एक लौह अयस्क खदान है जो स्पॉन्ज आयरन के उत्पादन के लिए जरूरतों की आंशिक भरपाई करती है।

विप्रो कंज्यूमर केयर की हुई कैनवे

समरीन अहमद
बेंगलूरु, 3 दिसंबर

- कंपनी का 16 साल में यह 12वां अधिग्रहण है
- कंपनी के अधिग्रहण पर अब तक 95 करोड़ डॉलर खर्च
- कैनवे ब्रांड का मूल्यांकन बिक्री के लिहाज से 2.1 करोड़ डॉलर है

आक्रामक अधिग्रहण की रणनीति जारी रखते हुए विप्रो कंज्यूमर केयर ऐंड लाइटिंग ने पर्सनल केयर कंपनी कैनवे का अधिग्रहण कर दक्षिण अफ्रीकी बाजार में प्रवेश कर लिया है।

बेंगलूरु मुख्यालय वाली कंपनी का 16 साल में यह 12वां अधिग्रहण है। कंपनी ने अधिग्रहण पर अब तक 95 करोड़ डॉलर खर्च किया है।

कंपनी के मुख्य कार्याधिकारी विनीत अग्रवाल ने कहा, हमारे लिए यह बेहतर है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की जीडीपी अफ्रीका दूसरे स्थान पर है और पूरे महाद्वीप में यह सबसे बड़ा पर्सनल केयर बाजार है। कंज्यूमर केयर कंपनी की अफ्रीका में मौजूदगी नहीं के बराबर है और इसका संतूर ब्रांड मिस्र और सूडान में उपलब्ध है।

इस अधिग्रहण के साथ विप्रो कंज्यूमर की पहुंच कैनवे के ब्रांड मसलन ओह सो हैवनली व अन्य ब्रांड तक हो जाएगी। सौदे के तहत कंपनी डरबन में कैनवे की विनिर्माण इकाई का भी अधिग्रहण करेगी। कैनवे ब्रांड का मूल्यांकन बिक्री के लिहाज से 2.1 करोड़ डॉलर है और दक्षिण अफ्रीकी पर्सनल केयर बाजार में इसके ब्रांडों की हिस्सेदारी करीब 30 फीसदी है।

अग्रवाल ने कहा, अधिग्रहीत कंपनी का क्लिक्स ब्रांड नामीबिया, सैशेल्स और घाना जैसे देशों में भी मौजूद है और क्लिक्स के विस्तार के साथ कैनवे का भी विस्तार होगा। यह अधिग्रहण विप्रो को कैनवे के उत्पाद दुनिया के अन्य हिस्सो में ले जाने में मदद करेगा और विप्रो उसके उत्पादों का पोर्टफोलियो भारत में भी लाने पर विचार कर रही है।

अग्रवाल ने कहा, आगे कंपनी का 55 फीसदी राजस्व अंतरराष्ट्रीय पोर्टफोलियो से आएगा। कंपनी के कुल राजस्व में अभी अंतरराष्ट्रीय बाजार करीब 51 फीसदी का योगदान करता है।

अमेरिकी टैरिफ पर ईयू संग पलटवार करेगा फ्रांस

रॉयटर्स
पेरिस, 3 दिसंबर

शैंपेन, हैंडबैग और अन्य फ्रांसीसी उत्पादों के 2.4 अरब डॉलर के आयात पर अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप 100 फीसदी शुल्क लगाते हैं तो फ्रांस और यूरोपीय यूनियन पलटवार करने के लिए तैयार है। फ्रांस की सरकार ने मंगलवार को ये बातें कही।

टैरिफ लगाने की धमकी तब तब सामने आई जब अमेरिकी सरकार की जांच में पाया गया कि फ्रांस की नई डिजिटल सेवा कर अमेरिकी तकनीकी कंपनियों को नुकसान पहुंचाएगी और इससे यूरोप व अमेरिका के बीच व्यापार विवाद गहरा जाएगा।

नाटो की बैठक से पहले मंगलवार को लंदन में ट्रंप ने कहा कि वह फ्रांस को अमेरिकी कंपनियों का फायदा नहीं उठाने देंगे और यूरोपीय यूनियन ने कारोबार पर अमेरिका के साथ काफी अनुचित व्यवहार किया।

फ्रांस के वित्त मंत्री ब्रूनो ली मेरे ने अमेरिकी धमकी को अस्वीकार्य है और फ्रांस का कर अमेरिकी कंपनियों के साथ विभेद नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा, अमेरिकी पाबंदी की स्थिति में यूरोपीय यूनियन पलटवार के तैयार रहेगा।

बाद में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम किसी देश पर निशाना नहीं साध रहे हैं।

फ्रांस का तीन फीसदी कर फ्रांस में कंपनियों की तरफ से डिजिटल राजस्व 2.5 करोड़ यूरो से ज्यादा अर्जित करने पर लागू होता है और दुनिया भर में 75 करोड़ यूरो राजस्व हासिल करने पर यह कर लगता है।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय की तरफ से हुई जांच में पाया गया कि फ्रांस का कर मौजूदा अंतरराष्ट्रीय कर नीति के सिद्धांतों के मुताबिक नहीं है। इसमें कहा गया है कि यह कर अमेरिका के लिए असामान्य तौर पर बोझ है। अल्फाबेट इंक गूगल, फेसबुक इंक, ऐपल इंक और एमेजॉन डॉट कॉम इंक जैसी कंपनियां इसमें शामिल हैं।

इरोस के हक में अदालती फैसला

बीएस संवाददाता
मुंबई, 3 दिसंबर

अमेरिका की एक अदालत ने भारत की फिल्म निर्माता कंपनी इरोस इंटरनैशनल मीडिया के पक्ष में फैसला दिया है। कंपनी ने शॉर्ट-सेलर्स के एक कंसोर्टियम के खिलाफ मुकदमा दायर कर उन पर आरोप लगाया था कि वह कंपनी के शेयर कीमतों के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। इरोस फिल्म निर्माण एवं वितरण कारोबार से जुड़ी कंपनी है। कंपनी की प्रमुख उत्पाद एवं सेवा मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग में हैं।

अदालत ने विशेष तौर पर मैनुएल एसेंसियो और एसेंसियो ऐंड कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला दिया क्योंकि उन्हें छह बार दस्तावेज भेजे जाने के बावजूद अदालत द्वारा निर्धारित समय-सीमा का अनुपालन नहीं किया। एसेंसियो निवेश फर्म एसेंसियो ऐंड कंपनी के संस्थापक, चेयरमैन एवं अध्यक्ष हैं। इस कंपनी की स्थापना 1992 में की गई थी।

अदालती फैसले का उल्लेख करते हुए इरोस के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक किशोर लूला ने कहा कि नुकसान का आकलन अगले चरण में किया जाना है लेकिन शॉर्ट-सेलिंग के कारण उल्लेखनीय क्षति हुई है। इरोज का शेयर मूल्य 2015 में 400 रुपये था जो घटकर 2019 में महज 15 रुपये रह गया है।

समाधान के लिए समय-सीमा के बारे पूछे जाने पर लूला ने कहा, 'हम आक्रामक तरीके से इस मामले को निष्कर्ष तक पहुंचाएंगे जिसमें अमेरिकी अदालतों में वर्षों लग सकते हैं।' लूला और इरोस ने शॉर्ट-सेलिंग करने वाले इस कंसोर्टियम के खिलाफ मामला 2017 में दायर किया था।

भारतीय बैंकों को होगी 7 अरब डॉलर की दरकार : फिच

अभिजित लेले
मुंबई, 3 दिसंबर

भारतीय बैंकों पर फिच रेटिंग ने अपने 2020 के आउटलुक में नकारात्मक परिदृश्य बरकरार रखा है।

वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने आज कहा कि एनबीएफसी के दबाव के मुकाबले भारतीय बैंकों के पास काफी कम प्रतिरोधक क्षमता है, जो एक और झटके को सहने के लिए काफी कम गुंजाइश का संकेत देता है। इन बैंकों को वित्त वर्ष 2021 में अपनी बढ़त को सहारा देने, फंसे कर्ज के लिए 75 फीसदी कवरेज और न्यूनतम बेसल-3 मानकों पर अतिरिक्त पूंजी के तौर पर अतिरिक्त 7 अरब डॉलर की दरकार होगी।

फिच ने एनबीएफसी का संकट बढ़ने के कारण बैंकों पर पड़ने वाले संभावित असर की जांच की। फिच ने कहा, हमारा अनुमान है कि इस परिदृश्य से नियामकीय अनिवार्यताएं पूरी करने के लिए बैंकों के पास 10 अरब डॉलर की कमी होगी।

रेटिंग एजेंसी ने आर्थिक अवरोध मसलन सुस्त होती अर्थव्यवस्था पर चेतावनी देते हुए कहा कि यह परिसंपत्ति गुणवत्ता पर और दबाव डाल सकता है।

एनबीएफसी का दबाव और आर्थिक अवरोध परिसंपत्ति गुणवत्ता के लिए और चुनौती खड़ी करेगा। यह चुनौती सार्वजनिक बैंकों के लिए ज्यादा है, जो पूंजी की कमी, फंसे कर्ज की वसूली में देरी और कमजोर आय का सामना कर रहे हैं। बैंकों को अपनी कमजोर बैलेंस शीट को देखते हुए और उधारी कारोबार में बढ़ोतरी बनाए रखने के लिए और पूंजी की जरूरत है।

सरकारी बैंकों को इसमें से सबसे ज्यादा पूंजी की दरकार होगी क्योंकि वित्त वर्ष 2020 में बैंकों में झोंके गए 10 अरब डॉलर नियामकीय पूंजीगत कमी की भरपाई में चले गए।

एचडीएफसी बैंक ने मांगी माफी

निधि राय
मुंबई, 3 दिसंबर

एचडीएफसी बैंक ने तकनीकी अवरोध के कारण ग्राहकों को नेट बैंकिंग व मोबाइल बैंकिंग ऐप के इस्तेमाल में हुई परेशानी के लिए माफी मांगी है, जहां दो दिन से ग्राहक दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। काफी ग्राहकों के लिए सोमवार सुबह 10 बजे से सेवाएं बाधित रहीं।

एचडीएफसी बैंक ने एक ट्वीट में कहा, तकनीकी अवरोध के कारण हमारे कुछ ग्राहकों को नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग ऐप पर लॉग-इन करने में परेशानी हुई। हमारे विशेषज्ञ इस पर काम कर रहे हैं और हमें भरोसा है कि जल्द ही सेवाएं बहाल हो जाएंगी। इस असुविधा के लिए हमें खेद है। बैंक के कई ग्राहकों ने ट्विटर पर इसकी शिकायत की। कई ग्राहकों ने कहा कि तकनीकी दिक्कत से वे अपनी सैलरी नहीं देख पा रहे हैं, जो एक तारीख को खाते में जमा हो जाती है। कई ग्राहकों की शिकायत थी कि वे तय अवधि में किया जाने वाला भुगतान नहीं कर पा रहे हैं।

एसबीआई एमएफ, आमुंडी का सीजी कंज्यूमर में हिस्सा

विवेट सुजन पिंटो
मुंबई, 3 दिसंबर

- पीई फंड एडवेंट और टेमासेक ने करीब 1,300 करोड़ रुपये के शेयर बेचे
- एसबीआई म्युचुअल फंड ने 750 करोड़ रुपये में 4.8 फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया

एसबीआई म्युचुअल फंड और एडवेंट ने प्राइवेट इक्विटी फर्मों एडवेंट और टेमासेक की तरफ से बेची गई 1,275 करोड़ रुपये की क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर की हिस्सेदारी (ब्लॉक डील के जरिए) में अहम हिस्सा खरीदा। एक ओर जहां एसबीआई म्युचुअल फंड ने 750 करोड़ रुपये में 4.8 फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया, वहीं आमुंडी इंडिया ने 1.44 फीसदी हिस्सेदारी 225 करोड़ रुपये में खरीदी।

एडवेंट इंटरनैशनल की अमलफियाको और टेमासेक की मैकरिची इन्वेस्टमेंट्स (दोनों प्रवर्तक इकाइयां) ने फर्म में अपनी हिस्सेदारी का क्रमश: 5.15 फीसदी और 3.01 फीसदी बेचा। 30 सितंबर 2019 में समाप्त तिमाही में अमलफियाको और मैकरिची के पास सीजी कंज्यूमर की क्रमश: 22.33 फीसदी और 12.03 फीसदी हिस्सेदारी थी, जो पहले गौतम थापर की अगुआई वाले अवंता समूह का हिस्सा थी। अप्रैल 2015 में अवंता समूह ने क्रॉम्पटन ग्रीव्स का उपभोक्ता कारोबार अलग कर पूरी 34.36 फीसदी हिस्सेदारी प्राइवेट इक्विटी फर्मों एडवेंट और टेमासेक को 2,000 करोड़ रुपये में बेच दिया था। मंगलवार को ब्लॉक डील के जरिये करीब 5.1 करोड़ शेयरों का लेनदेन हुआ और इसकी कीमत 249.2 रुपये प्रति शेयर रही, जो सीजी कंज्यूमर के मौजूदा बाजार भाव 246.2 रुपये प्रति शेयर से ज्यादा है।

एसबीआई म्युचुअल और आमुंडी के अलावा ब्लॉक डील में शामिल अन्य निवेशक थे सिटीग्रुप, फिडेलिटी, मॉर्गन स्टैनली एशिया व सोसियाते जेनराली।

उबर को 200 शहरों तक ले जाएगी बाइक-टैक्सी

सुरजीत दास गुप्ता
नई दिल्ली, 3 दिसंबर

दायरे में विस्तार

- उबर विभिन्न शहरों के बीच अपना परिचालन चार गुना बढ़ाने की बना रही योजना
- वर्ष 2020 के लिए कंपनी की नजर बाइक साझेदारी सेवा, तिपहिया वाहनों पर रहेगी
- परिवहन सेवा के लिए स्थानीय कारोबारियों से साझेदारी करेगी उबर
- कार-हेलिंग सेवाओं से लाभप्रदता को मिलेगी रफ्तार

अजय मोहंती

उबर इंडिया ने अपने परिचालन में चार गुना विस्तार करने की योजना बनाई है। इसके तहत कंपनी अगले साल के अंत तक अपनी मौजूदगी 200 शहरों तक बढ़ाएगी जो फिलहाल 52 शहरों तक है। इस विस्तार को कार-हेलिंग से नहीं बल्कि बाइक-टैक्सी सेवा से रफ्तार मिलेगी। कंपनी ने इसी साल जुलाई में इस सेवा की शुरुआत की थी। फिलहाल इस प्रकार की सेवाएं 30 शहरों में शुरू की गई हैं जिसके तहत रोजाना 1,50,000 ट्रिप का संचालन किया जा रहा है। लेकिन वह महाराष्ट्र और कर्नाटक के बड़े शहरों में मौजूद नहीं है जहां वह फिलहाल नियामकों के साथ काम कर रही है।

तिपहिया इस पहल का हिस्सा होगा। उबर के अध्यक्ष (भारत एवं दक्षिण एशिया) प्रदीप परमेश्वरण ने अगले साल के लिए भारत में कंपनी की रणनीति के बारे में बताते हुए कहा, 'हमारी पहल प्रीमियम एसी-कार बाजार से आगे बढ़ने की है जो बाजार के ऊपरी तबके पर आधारित है। मध्यम एवं आम लोगों के बाजार में प्रौद्योगिकी नाटकीय भूमिका निभा सकती है। इससे पहले हमारे पास कोई ऐसा उत्पाद नहीं था जो शहरों के बाहर के लोगों के लिए प्रासंगिक हो। भारत में लोग केवल कारों से ही नहीं चलते बल्कि वे दोपहिया, तिपहिया और बसों की भी सवारी करते हैं।'

हालांकि किराये पर कार लेने की सेवा इनमें से अधिकतर शहरों में उपलब्ध रहेगी लेकिन यदि नियामकीय मंजूरी मिल गई तो इन सभी शहरों में दोपहिया सेवा शुरू की जाएगी। कंपनी के अध्यक्ष ने कहा, 'कार कुछ रूपों में उपलब्ध रहेगी लेकिन उबर जोर आम लोगों के उत्पादों पर रहेगा न कि प्रीमियम एसी कारों पर।'

कंपनी इसके लिए उन स्थानीय कारोबारियों के साथ साझेदारी करना चाहती है जो इसी तरह के कारोबार से जुड़े हैं और उबर प्लेटफॉर्म पर आना चाहते हैं। इस पहल का एक बड़ा हिस्सा तिपहिया वाहन होंगे। पिछले साल के मध्य में इस सेवा की शुरुआत करने के बाद उबर रोजाना 4 लाख से अधिक राइड का संचालन करती है। वह शहरों के भीतर बस सेवा भी शुरू कर सकती है। लेकिन अभी यह निर्णय नहीं लिया गया है कि बस सेवा अगले साल से शुरू की जाएगी अथवा नहीं।

कार-हेलिंग कारोबार के भविष्य के बारे में बताते हुए परमेश्वरन ने कहा, 'कार बाजार में वृद्धि की रफ्तार सुस्त पड़ गई है और वह आज हमारे पोर्टफोलियो में जो भूमिका निभा रही है उससे लाभप्रदता में तेजी आ सकती है।'

जब उनसे पूछा गया कि सवारी के लिए कारें छोटी होंगी तो उन्होंने कहा कि ट्रिप की संख्या (केवल शहरों के भीतर) के आधार पर हरेक तीन में से दो ट्रिप में छोटी कारों का इस्तेमाल होता है जो साल की शुरुआत में हरेक छह में से पांच ट्रिप में छोटी कारों का इस्तेमाल होता था।

बिना एसी वाली कार क्षेत्र में कंपनी को काफी संभावनाएं दिख रही हैं। फिलहाल उसने 100 वाहनों के साथ क्यूट (क्वाड्रिसाइकल) के लिए बजाज ऑटो के साथ एक परियोजना परीक्षण के तौर पर शुरू की है। उन्होंने कहा कि इसका विस्तार अन्य बाजारों में भी करने की योजना है क्योंकि सवारी और उपयोगकर्ता दोनों की प्रतिक्रिया काफी उत्साहजनक रही है।

परमेश्वरन ने कहा कि बाइक के लिए संभावनाएं काफी अधिक हैं क्योंकि देश में 10 करोड़ से अधिक दोपहिया वाहन मौजूद है जो इस प्रकार के वाहनों का सबसे बड़ा विनिर्माता थी। उन्होंने कहा कि इस बाजार की क्षमता और उसके आकार के बारे में बताते हुए कहा कि इंडोनेशिया में बाइक राइड-हेलिंग सेवा गोजेक ने प्रति सप्ताह 2 करोड़ से अधिक राइडों का संचालन किया जबकि भारत के मुकाबले उस देश की आबादी महज 25 फीसदी है। उन्होंने कहा कि कारोबार के लिहाज से बाइक-टैक्सी सेवा बिल्कुल उपयुक्त है क्योंकि लोग छोटे ट्रिप के लिए इसका उपयोग करते हैं जो आमतौर पर 20 मिनट से कम समय की सवारी होती है।

बाइक-टैक्सी सेवा से जुड़कर ड्राइवर 10 से 15 हजार रुपये महीना कमा सकते हैं। ड्राइवर साझेदार अपनी बाइक को भी इस प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं।

कार्वी के खिलाफ सैट पहुंचे तीन बैंक

जश कृपलानी
मुंबई, 3 दिसंबर

निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और इंडसइंड बैंक ने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के डीमैट खाते से संबंधित क्लाइंटों को प्रतिभूतियां हस्तांतरित करने के नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी (एनएसडीएल) कदम के खिलाफ प्रतिभूति अपील पंचाट (सैट) का दरवाजा खटखटाया। एक दिन पहले बजाज फाइनैंस ने इसी तरह के मामले में पंचाट का दरवाजा खटखटाया था।

इन लेनदारों ने कार्वी को संयुक्त रूप से करीब 1,000 करोड़ रुपये उधार दिए हैं, जिसने इस कर्ज के लिए क्लाइंटों की प्रतिभूतियों का इस्तेमाल जमानत के तौर किया है।

एचडीएफसी बैंक के पास 470 करोड़ रुपये के गिरवी शेयर हैं, जो 300 करोड़ रुपये के बकाया कर्ज के लिए है। बाजाज फाइनैंस का कार्वी के पास 345 करोड़ रुपये बकाया है। अन्य लेनदारों के कर्ज का आकलन नहीं किया जा सका।

लेनदारों के वकीलों ने गिरवी शेयर क्लाइंटों के खाते में वापस हस्तांतरित करने के एनएसडीएल के फैसले पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि बाजार नियामक सेबी का 22 नवंबर का आदेश यथास्थिति बनाए रखने के लिए था।

एचडीएफसी बैंक के वकील ने कहा कि सैट को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और अब क्लाइंटों के खाते में हस्तांतरित प्रतिभूतियों से जुड़े लेनदेन को रोक देना चाहिए। वकील ने कहा, करीब 400 करोड़ रुपये के गिरवी शेयर स्वाहा हो गए।

वकीलों ने कहा कि क्लाइंटों के खाते में वापस शेयरों का हस्तांतरण सेबी के डिपॉजिटरी अधिनियम का उल्लंघन है। वरिष्ठ वकील सोमशेखर सुंदरेशन ने एनएसडीएल का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा कि डिपॉजिटरी ने सेबी के आदेश के मुताबिक कदम उठाया। साथ ही सेबी से संपर्क के बाद ही डिपॉजिटरी ने कदम बढ़ाया। उन्होंने कहा, एनएसडीएल के रिकॉर्ड में कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग का खाता नॉन-हाउस खाता है, जो संकेत देता है कि यह ब्रोकर का खुद का खाता नहीं है। ऐसे में बैंकों को जागरूक रहना चाहिए कि यह क्लाइंटों का खाता है।

सैट के पीठ ने तमाम दलीलें सुनने के बाद बुधवार के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया। पंचाट ने हालांकि बजाज फाइनैंस के मामले में आदेश पारित किया, जहां ऐसे ही तर्क व जवाबी तर्क एक दिन पहले पेश किए गए थे।

सैट ने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य को बजाज फाइनैंस की व्यक्तिगत सुनवाई करने और 10 दिसंबर तक आदेश पारित करने को कहा है। सैट ने पाया कि सेबी के आदेश से बजाज फाइनैंस के अधिकारों पर प्रतिकूल असर पड़ा। ट्रिब्यूनल ने कार्वी के डीमैट खाते से क्लाइंटों के खाते में और प्रतिभूतियां हस्तांतरित करने पर रोक लगा दी। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि पंचाट अन्य लेनदारों के मामले में ऐसा ही आदेश पारित कर सकता है।

कानूनी लड़ाई

- बजाज फाइनैंस के कदम के बाद एनएसडीएल, सेबी के खिलाफ और लेनदार जुड़े
- आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक ने क्लाइंटों के खाते में गिरवी शेयर लौटाने पर सवाल उठाया
- कुल मिलाकर इन लेनदारों के पास कार्वी ने करीब 1,000 करोड़ रुपये के शेयर गिरवी रखे थे
- सैट इस मामले में बुधवार को जारी कर सकता है निर्देश

लाइसेंस निलंबन पर सैट पहुंची कार्वी

कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग ने ब्रोकिंग लाइसेंस निलंबित करने के एनएसई के फैसले के खिलाफ सैट में एक और याचिका दाखिल की है। कार्वी के वकील विक्रम ननकानी ने वैसे समय में ब्रोकरेज की सदस्यता निलंबित करने के एक्सचेंज के फैसले पर सवाल उठाया है जब सेबी के 22 नवंबर के अंतरिम आदेश में इस तरह का कोई निर्देश नहीं दिया गया है। वकील ने कहा कि कार्वी की सदस्यता निलंबित करना उसके मौजूदा क्लाइंटों के लिए नुकसानदायक है। इस मामले का निपटारा करते हुए सैट ने कार्वी को एनएसई की अनुशासन समिति से संपर्क करने को कहा है।

अगले साल के लिए गोल्डमैन का निफ्टी लक्ष्य 13,000

गोल्डमैन सैक्स को उम्मीद है कि अगले साल बेंचमार्क निफ्टी-50 इंडेक्स 13,000 तक पहुंच जाएगा। यह मौजूदा स्तर से करीब 8 फीसदी की बढ़ोतरी दर्शाता है। मंगलवार को निफ्टी 11,994 पर बंद हुआ। ब्रोकरेज हालांकि 2020 में कंपनियों की आय 16 फीसदी बढ़ने का अनुमान लगा रहा है, जो 20 फीसदी की बढ़ोतरी के आमराय से नीचे है।

गोल्डमैन सैक्स के प्रमुख इक्विटी रणनीतिकार (एशिया-प्रशांत क्षेत्र) टिमोथी मो ने कहा, लाभ में नरम बढ़ोतरी की पृष्ठभूमि में 2019 में प्रदर्शन अच्छा रहा है। ऐसे में 2020 में भी प्रदर्शन ठीक रहने की संभावना है। गोल्डमैन सैक्स के लिए उभरते बाजारों (एशिया) चीन और दक्षिण कोरिया समेत भारत सबसे ज्यादा ओवरवेट बना हुआ है। इस साल अब तक एमएससीआई एशिया प्रशांत (जापान को छोड़कर) 12 फीसदी चढ़ा है। हालांकि अमेरिकी एसऐंडपी-500 इंडेक्स 24 फीसदी चढ़ा है। परिदृश्य हालांकि साल 2020 के लिए सकारात्मक है। *बीएस*

ऐलान के बिना बाजार से बॉन्ड खरीद रहा आरबीआई

बैंकिंग व्यवस्था में नकदी की भरमार है, वहीं भारतीय रिजर्व बैंक बिना ऐलान के द्वितीयक बाजार से लगातार बॉन्डों की खरीद कर रहा है। मंगलवार को बैंकों ने 3.05 लाख करोड़ रुपये की अपनी अतिरिक्त रकम आरबीआई के पास जमा कराई, जो नोटबंदी के दिनों के बाद का सर्वोच्च आंकड़ा है। भारी-भरकम नकदी के परिचालन के लिए केंद्रीय बैंक को बॉन्ड चाहिए। ये बॉन्ड बैंकों को उनकी नकदी के बदले जमानत के तौर दिए जाते हैं। जून 2019 के आखिर में आरबीआई के पास करीब 9.9 लाख करोड़ रुपये के बॉन्ड थे। इसकी वजह यह है कि आरबीआई ने वित्त वर्ष 19 में बैंकिंग व्यवस्था में नकदी झोंक लाख करोड़ रुपये तक के बॉन्ड बैंक चूंकि उधार देने पूरी नकदी आरबी हैं, लिक

कंपनी मंत्रालय ने समाधान पेशेवरों को आईबीसी के दौरान कंपनी की फाइलिंग का अधिकार दिया

दिवाला कंपनियों को बड़ी राहत

रुचिका चित्रवंशी
नई दिल्ली, 3 दिसंबर

दिवाला प्रक्रिया से गुजर रही कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए कंपनी मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने समाधान पेशेवरों (आरपी) को कंपनी के नियमित अनुपालन दाखिल करने का अधिकार दे दिया है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड को यह जानकारी दी। यह बड़ी चुनौती बन गई थी क्योंकि कंपनी को दिवाला प्रक्रिया में डाले जाने के साथ ही निदेशक मंडल के अधिकार खत्म हो जाते हैं और इसकी वजह से कुछ नियमित फाइलिंग कठिन हो जाती है।

वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'अगर कोई कंपनी कॉर्पोरेट दिवाला, समाधान, परिसमापन या विघटन की प्रक्रिया से गुजर रही है तो उसकी स्थिति एमसीए के मास्टर डेटा में नजर आएगी। आरपी को अधिकार होगा कि वे सभी वित्तीय लेखा जोखा और सालाना रिटर्न सहित सभी फाइलिंग कर सकेंगे।'

एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कंपनी मामलों का मंत्रालय आरपी के डिजिटल हस्ताक्षर को भी अनुमति देगा और उन्हें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का दर्जा होगा।

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलली) के दिल्ली पीठ ने 22 नवंबर 2019 के अपने आदेश में कंपनी के पंजीयक को निर्देश दिए थे कि वह कॉर्पोरेट कर्जदार का मास्टर डेटा अद्यतन करे, जिससे कि कंपनी की स्थिति के बारे में आम लोगों को सूचना मिल सके, जो कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया आई है और उनके आंकड़े संकलित नहीं किए गए हैं।

आईबीसी की स्थिति में समाधान पेशेवर सूचीबद्ध कंपनी की रोजमर्रा के मामलों का प्रभार लेते हैं और उन्हें यह अधिकार नहीं था कि वे ऑडिट और बगैर ऑडिट वाले वित्तीय परिणम पर हस्ताक्षर कर उन्हें अपलोड कर सकें।

एनसीएलटी के पीठ ने सिक्का पेपर के मामले में यह आदेश पारित किया था और आरओसी को एक सप्ताह का वक्त दिया था कि वह इस मसले पर शपथपत्र दायर करे कि आरपी को दस्तावेजों अपलोड करने की अनुमति क्यों नहीं है, अगर निदेशक मंडल को धारा 14 के तहत अधिस्थगन लागू होने के बाद निलंबित कर दिया गया है। पीठ ने आरओसी से कहा था कि सालाना बही खाते जैसे आंकड़े अपलोड करने की वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर स्थिति साफ करे।

कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स के पार्टनर मनोज कुमार ने कहा, 'यह व्यावहारिक कठिनाई है। बोर्ड की शक्तियां आरपी को चली जाती हैं। जबकि निलंबित किए गए बोर्ड के निदेशक इसके बावजूद हस्ताक्षर कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगर वे सहयोग नहीं करते हैं तो यह मुसीबत बन जाता है।'

वहीं समाधान प्रक्रिया में यह भी चुनौती है कि अगर कॉर्पोरेट कर्जदार ने पुरानी फाइलिंग नहीं की है तो वह नए अधिग्रहणकर्ता के लिए समस्या है। पीडब्ल्यूसी में पार्टनर अंशुल जैन ने कहा, 'जब तक कंपनी अपनी पहले की सभी फाइलिंग नहीं कर देती है, नई फाइलिंग नहीं की जा सकती।' उन्होंने यह भी कहा कि एक बार जब मामले का समाधान हो जाता है, नए निदेशक को जिम्मेदारी संभालनी होती है लेकिन उसे नियुक्त कौन करेगा क्योंकि निगरानी समिति या कर्जदाता को ऐसी शक्तियां हैं, यह इस मामले में स्थिति साफ नहीं है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एनपीए के रूप में आईबीसी के पास भेजे गए एक बड़े मामले में नए प्रबंधन ने सरकार के उच्च स्तर पर यह मामला उठाया कि नियमित अनुपालन को लेकर स्थिति साफ की जाए। इस मामले से जुड़े एक व्यक्ति ने कहा, 'सीआरआईपी में जाने के पहले दो साल तक आरओसी के साथ पूर्ववर्ती कंपनी ने अपनी फाइलिंग नहीं की। इसकी वजह से नए प्रबंधन के लिए यह कठिन हो गया कि वह कंपनी की नए सिरे से शुरुआत करे।'

साफ हुई स्थिति

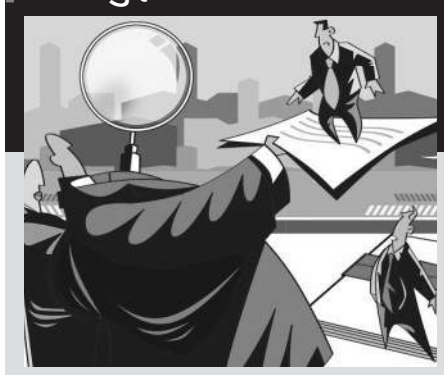

अगर कॉर्पोरेट कर्जदार ने पुरानी फाइलिंग न की हो तो नए प्रबंधन को आती थीं मुश्किलें

- कंपनी के आईबीसी प्रक्रिया में आने के बाद सामान्य फाइलिंग में हो रही थी दिक्कत
- सरकार ने दिवाला पेशेवरों को फाइलिंग के साथ डिजिटल हस्ताक्ष करने का भी अधिकार दिया
- अब दिवाला प्रक्रिया में चल रही कंपनी की फाइलिंग आसान

कंपनी से 170 करोड़ रु लेने पर कांग्रेस को नोटिस

भाषा
नई दिल्ली, 3 दिसंबर

आयकर विभाग ने कांग्रेस को एक कंपनी से 170 करोड़ रुपये की निधि कथित तौर पर लेने पर स्पष्टीकरण मांगते हुए एक नोटिस भेजा है। विभाग ने 3,300 करोड़ रुपये के हवाला रैकेट मामले में कर चोरी की जांच के सिलसिले में यह नोटिस भेजा है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि इस मामले में आगे की जांच के लिए यहां पार्टी को नोटिस भेजा गया है। बुनियादी ढांचा क्षेत्र के अग्रणी कॉरपोरेट घरानों से जुड़े कई परिसरों पर दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद में छापों के बाद इस मामले का खुलासा हुआ था। अधिकारियों के मुताबिक, यह निधि हैदराबाद स्थित मेगा इन्फ्रास्ट्रक्चर ऐंड इंजीनियरिंग ने कांग्रेस को भेजी थी। उन्होंने बताया कि आयकर विभाग की नजर इस मामले में कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी और आंध्र के एक राजनीतिक दल पर भी है।

आय कर विभाग के लिए नीति बनाने वाले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने नंवबर में एक बयान में कहा था कि कर चोरी के बड़े गिरोह का खुलासा करने के लिए ये छापे महीने के पहले सप्ताह में मारे गए थे। बयान में कहा गया था कि फर्जी बिल जारी करने और हवाला लेनदेन करने वाले लोगों के एक समूह पर दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, इरोड, पुणे, आगरा और गोवा में 42 स्थानों पर छापे मारे गए थे। सीबीडीटी ने कहा था, आपराधिक सबूतों का खुलासा, कॉरपोरेट्स, हवाला संचालकों के बीच गठजोड़ का पता लगाने के लिए तलाश अभियान सफल रहा।

उपभोक्ता व्यय रिपोर्ट पर सांख्यिकी आयोग में चर्चा

सोमेश झा
नई दिल्ली, 3 दिसंबर

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएससी) बुधवार को उपभोक्ता खर्च के आधिकारिक सर्वेक्षण पर चर्चा के लिए बैठक करेगा। यह बैठक सरकार की ओर से उपभोक्ता खर्च पर आई इस सर्वेक्षण को खारिज करने के निर्णय के बाद उपजे विवाद के मद्देनजर बुलाई गई है।

विवाद के बाद बैठक

इस मामले के जानकार एक व्यक्ति के मुताबिक बैठक में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की ओर से किए गए सर्वेक्षण के आंकड़ों की गुणवत्ता का मसला एनएससी के एजेंडे में शीर्ष पर होगा। देश की सांख्यिकीय प्रणाली पर नजर रखने वाला एनएससी एक स्वायत्त संस्था है। इसके अध्यक्ष क्रिप्टोलॉजिस्ट बिमल कुमार रॉय हैं।

2017-18 के उपभोक्ता खर्च सर्वेक्षण को सरकार द्वारा रद्द करने के निर्णय के बाद एनएससी की यह पहली बैठक है। माना जा रहा है कि एनएसओ के अधिकारी एनएससी सदस्यों को सर्वेक्षण को रद्द करने के सरकार के निर्णय और विभिन्न सर्वेक्षणों में पाए गए आंकड़ों की गुणवत्ता के मामले पर एक प्रतिवेदन दे सकते हैं।

बिजनेस स्टैंडर्ड ने 15 नवंबर को खबर दी थी कि सही अर्थों में उपभोक्ता खर्च में पहली गिरावट 2011-12 और 2017-18 के दौरान आई। घरेलू उपभोग सर्वेक्षण के एनएसओ के प्रमुख संकेतकों के मुताबिक चार दशकों में पहली बार इसमें 3.7 फीसदी की कमी दर्ज की गई। विशेषज्ञों की राय में इसका मतलब यह है कि विगत कई दशकों में पहली बार गरीबी अनुपात में वृद्धि होने की आशंका है। इस मामले के जानकार चार लोगों ने कहा कि इस रिपोर्ट को कार्यसमूह की ओर से जून में ही जारी करने की मंजूरी दी गई थी लेकिन इसके खराब नतीजों को देखते हुए इसे जारी करने नहीं दिया गया। इसकी खबर आने के बाद 15 नवंबर को सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा था कि इस सर्वेक्षण के आंकड़ों की गुणवत्ता को देखते हुए उसने इस रिपोर्ट को रद्द करने का निर्णय लिया है।

19 जून को कार्यसमूह की मंजूरी के बाद सांख्यिकी मंत्रालय को उपभोक्ता खर्च सर्वेक्षण रिपोर्ट को एनएससी की मंजूरी के लिए उसके पास भेजना था। हालांकि, बिजनेस स्टैंडर्ड द्वारा देखे गए दस्तावेजों के मुताबिक सर्वेक्षण के नतीजों को एनएससी की मंजूरी के लिए भेजने की बजाय जो कि प्रक्रिया का हिस्सा है, सांख्यिकी सचिव और मुख्य सांख्यिकीविद् प्रवीण श्रीवास्तव ने 11 जुलाई को एनएसओ अधिकारियों के साथ एक बैठक की जिसमें रिपोर्ट के नतीजों पर चर्चा की गई।

भगोड़ों ने 17,900 करोड़ रु चूना लगाया

आर्थिक अपराध कर देश छोड़कर भागने वाले 51 लोगों ने कुल मिलाकर 17,900 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राज्यसभा में कहा, 'केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बताया है कि आज तक, 66 मामलों में 51 फरार और घोषित अपराधी अन्य देशों में भाग गए हैं।' *भाषा*

डेलॉयट सिर्फ 1 रुपये लेगी फीस

शाइन जैकब
नई दिल्ली, 3 दिसंबर

- बीपीसीएल के के विनिवेश में लेन देन सलाहकार के रूप में डेलॉयट लेगी सिर्फ 1 रुपये शुल्क
- जानकारों का कहना है कि कंपनी अपना पोर्टफोलियो मजबूत करने और साख बढ़ाने के लिए दे रही सेवा

भारत के सबसे बड़े रणनीतिक विनिवेश के लेन देन सलाहकार के रूप में डेलॉयट ने 1 रुपये शुल्क पर सेवाएं देने की पेशकश की है। डेलॉयट टचे तोमात्सू इंडिया ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) की बिक्री के लिए 1 रुपये में सेवाओं की पेशकश की है। इस रणनीतिक बिक्री से सरकार को 70,000 से 80,000 करोड़ रुपये मिलने की संभावना है।

इस मामले से जुड़े 3 व्यक्तियों ने बताया कि एसबीआई कैपिटल ने दूसरी सबसे छोटी बोली करीब 15-17 करोड़ रुपये की लगाई है।

इस सिलसिले में डेलॉयट और एसबीआई कैपिटल ने भेजे गए ई मेल का कोई जवाब नहीं दिया। एक व्यक्ति ने कहा, 'डेलॉयट के लिए यह सम्मान के लिए सौदा हो सकता है और वह अपनी पोर्टफोलियो में एक राष्ट्रीय ऊर्जा कंपनी को जोड़ सकेगी।' सरकार ने संपत्ति के मूल्यांकन के लिए 50 दिन का वक्त रखा है क्योंकि वह पूरी प्रक्रिया 31 मार्च 2020 के पहले पूरी करना चाहती है।

डेलॉयट और एसबीआई कैप्स ने 28 नवंबर को विनिवेश एवं संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सामने अपनी प्रस्तुतियां दी थी, जिसके बाद डेलॉयट को सफल बोलीकर्ता के रूप में चुना गया था। डेलॉयट कंटेनर कॉर्पोरेशन आफ इंडिया (कॉनकॉर) के लिए भी इसी तरह की कम बोली लगा सकती है, जो 0.01 से 1 प्रतिशत के बीच हो सकती है।

निवेश बैंकर द्वारा शून्य के करीब बोली लगाने की शुरुआत कोल इंडिया (सीआईएल) की 15,000 करोड़ रुपये के आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के समय एक दशक पहले शुरू हुई थी। सिटी बैंक ने बहुत कम अंशधारिता की पेशकश की खथी और अन्य 5 बोलीकर्ताओं ने भी अब तक के सबसे बड़े आईपीओ की प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए बहुत मामूली बोली लगाई थी। सीआईएल के एख पूर्व अधिकारी ने कहा कि उस समय सलाहकारों को सिर्फ 1500 रुपये दिए गए थे, जबकि उन्होंने दुनिया के 14 शहरों में रोड शो सहित पूरी प्रक्रिया का प्रबंधन किया था।

आईपीओ जारी किए जाने के वक्त सीआईएल के चेयरमैन रहे पार्थ भट्टाचार्य ने कहा, 'वे नकदी की तरफ नहीं देखते, बल्कि वे काम पाते हैं और देखते हैं कि इससे उनकी कितनी साख बनेगी। डेलॉयट को संभवत: नहीं पता रहाहोगा कि अगला बोलीकर्ता कितनी बोली लगाएगा और उसने इस सौदे के साथ अपना नाम जोडने के लिए एक सांकेतिक राशि में सेवाएं देने की पेशकश कर दी।'

आक्रामक बोली के एक और मामले जेएम फाइनैंशियल ने तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) द्वारा हिंदुस्तान पेट्रोलिमय कॉर्पोरेशन लिमिटेड की खरीद में सिर्फ 1 रुपये बोली लगाई थी।

अब डेलॉयट के सामने सबसे बड़ी चुनौती समय के भीतर काम पूरा करना है। उद्योग के सूत्रों ने कहा कि बिक्री के लिए रुचि पत्र भी मूल्यांकन प्रक्रिया के साथ ही जारी किया जा सकता है, जिससे कि प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।

ऑनलाइन दवा बिक्री पर गिरेगी गाज

पृष्ठ 1 का शेष

हालांकि उद्योग की राय कुछ और ही है। एक अग्रणी ई-फार्मेसी के वरिष्ठ कार्याधिकारी ने कहा कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) जब तक इस बारे में औपचारिक अधिसूचना जारी नहीं करता है और चिकित्सकों की पर्ची के जरिये ऑनलाइन दवा की बिक्री पर रोक नहीं लगाई जाती है, वे पुराने मॉडल के तहत परिचालन जारी रख सकते हैं। एक अग्रणी ई-फार्मेसी के संस्थापक ने कहा, 'जब यह अधिसूचना आएगी तो हम उसे कानून के तहत चुनौती देंगे।' उनका तर्क है कि औषधि एवं कॉस्मैटिक्स अधिनियम, 1940 में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चिकित्सकों की पर्चियां जेनरेट करने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

एक अन्य वरिष्ठ कार्याधिकारी ने कहा, 'अगर सरकार किसी तरह का बंदिश लगाती है तो हम निश्चित तौर पर उसे अदालत में चुनौती देंगे। अगर आप इसका पालन करते हैं तो फिर फोन या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सऐप के माध्यम से ऑर्डर लेना औषधि एवं कॉस्मैटिक्स अधिनियम के दायरे में नहीं आएगा, जबकि दवा दुकानदारों द्वारा इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जाता है।'

पिछले साल दिसंबर में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि बिना लाइसेंस दवाओं की ऑनलाइन बिक्री उचित नहीं है और उसने सरकार को इस पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। दूसरी ओर मद्रास उच्च न्यायालय ने ई-फार्मेसी कंपनियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस पाबंदी को हटा दिया था।

ई-फार्मेसी कंपनियों का मानना है कि इस क्षेत्र के लिए व्यापक दिशानिर्देश की जरूरत है। एक ऑनलाइन फार्मेसी के मुख्य कार्याधिकारी ने कहा, 'मौजूदा समय में कारोबार पूरी तरह से वैध है और आईटी अधिनियम और औषधि एवं कॉस्मैटिक्स अधिनियम के दायरे में आता है। हालांकि निवेशकों और ग्राहकों के बीच भरोसा बढ़ाने के लिए क्षेत्र में नियमन की जरूरत है।'

मसौदा नियमों के अनुसार केवल सरकार में पंजीकृत ई-पोर्टल ही दवाओं की बिक्री कर सकते हैं। उन्हें दवा की पर्चियों को सहेज कर रखना होगा और मरीजों एवं चिकित्सकों के विवरण का सत्यापन भी करना होगा।

डिजिटल हेल्थ उद्योग के उद्यमियों का संगठन डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म्स ने राजधानी दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में नियमों को अधिसूचित करने में देरी को लेकर चिंता जताई।

1एमजी के संस्थापक एवं मुख्य कार्याधिकारी प्रशांत टंडन ने कहा, 'हम नियामकों और मंत्रालयों के साथ पिछले चार साल से बातचीत कर रहे हैं और इस मसले पर कई हितधारकों के साथ चर्चा में हिस्सा लिया है। मंत्रालय ने बीते अगस्त में ई-फार्मेसी पर मसौदा अधिसूचना जारी की थी। हालांकि इस क्षेत्र के लिए अब तक स्पष्ट नियामन नहीं बन पाया है।' उद्योग का दावा है कि इस क्षेत्र ने 30,000 से ज्यादा रोजगार का सृजन किया है और इसमें करीब 70 करोड़ डॉलर का निवेश हुआ है। नेटमेड्स के संस्थापक एवं मुख्य कार्याधिकारी प्रदीप डडाह ने कहा कि वे प्रधानमंत्री के आयुष्मान भारत योजना का हिस्सा बनना चाहते हैं। अधिकतर ऑनलाइन फार्मेसी अपना ऑफलाइन मौजूदगी का विस्तार करने पर भी ध्यान दे रही हैं और ओम्नी चैनल विकसित कर रही है।

बैंक डूबने पर भारत में कम वापसी

सुब्रत पांडा
नई दिल्ली, 3 दिसंबर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि भारत का डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर ब्रिक्स देशों में सबसे कम है। वित्त मंत्री ने कहा, 'भारत में प्रति व्यक्ति आय के अनुपात में डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर 31 मार्च 2019 को 0.8 था, जो दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर अन्य ब्रिक्स देशों की तुलना में कम है।'

ब्राजील में इसके उलट डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर और प्रति व्यक्ति आय का अनुपात 8.5 है। वहीं चीन में यह अनुपात 7.4 और रूस में 2.2 है। भारत का डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर 1 लाख रुपये या करीब 1,407 डॉलर आता है। जमाकर्ता अपने खाते में चाहे जितना जमा करे, उसे अधिकतम 1 लाख रुपये बीमा सुरक्षा मिलती है। इसकी तुलना में ब्राजील में डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर सबसे ज्यादा 75,588 डॉलर है, जबकि चीन में 72,690 डॉलर, रूस में 24,306 डॉलर है। वहीं दक्षिण अफ्रीका में जमा बीमा व्यवस्था लागू करने की प्रक्रिया चल रही है।

2018-19 में भारतीय रिजर्व बैंक की पूरी तरह से सहायक इकाई जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी), जो बैंक जमा पर बीमा मुहैया कराती है, ने कुल 12,040 करोड़ रुपये प्रीमियम इकट्ठा किया था, जिनमें से वाणिज्यिक बैंकों ने 11,190 करोड़ रुपये प्रीमियम दिया था और सहकारी बैंकों ने 850 करोड़ रुपये प्रीमियम का भुगतान किया था।

इसके अलावा डीआईसीजीसी ने 2018-19 में 15 सहकारी बैंकों के 40 करोड़ रुपये के दावों का निपटान किया था। इसमें 2 सहकारी बैंकों का 3.05 करोड़ रुपये का निपटान शामिल है। पंजाब ऐंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक (पीएमसी) की घटना के बाद पर्याप्त डिपॉजिट इंश्योरेंस न होना चिंता का विषय हो गया है।

बीएस सूडोकू 3603

परिणाम संख्या 3602

3					4	2		8
9			3					1
			2		5	6		3
7	3						4	
		9				1		
	6						2	7
4		8	7		3			
2					9			4
6		7	5					2

7	2	6	5	8	1	9	3	4
1	9	5	2	4	3	6	8	7
8	3	4	7	9	6	2	1	5
9	1	3	6	7	4	8	5	2
4	6	8	1	2	5	7	9	3
5	7	2	9	3	8	4	6	1
6	4	9	3	5	7	1	2	8
3	8	1	4	6	2	5	7	9
2	5	7	8	1	9	3	4	6

कैसे खेलें?
हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

मुश्किल
★★★★☆

एनसीएलटी के पीठों में 19,771 मामले

सरकार ने मंगलवार को बताया कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) की विभिन्न पीठों के समक्ष 30 सितंबर 2019 तक कुल 19,771 मामले लंबित थे। वित्त और कार्पोरेट कार्य राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि एनसीएलटी द्वारा मुहैया कराए गए आंकड़ों के अनुसार 30 सितंबर 2019 को उसकी विभिन्न पीठों के समक्ष कुल 19,771 मामले लंबित थे। इनमें से 10,860 मामले दिवाला व शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अंतर्गत हैं। *भाषा*

क्षेत्रीय मंडियों के भाव

उत्तर प्रदेश | राजस्थान | पंजाब

कानपुर
गेहूं लूज 2110/2120, जौ 1790/1800, चावल मसूरी 2275/2325, चावल मोटा 2150/2250, सरसों 4300/4325, तिल सफेद 9000/9100, सोया (टीन) 1450/1500, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन)1530/1600, सरसों खल 2250/2350, पामोलिन 1400/1450,

लखनऊ
गेहूं दड़ा 2100/2125, गेहूं शरबती 2700/2800, चावल शरबती सेला 3800/3900, स्टीम 4300/4400, लालमती 3300/3400, चावल (सोना) 2950/3000,

चंदौसी
(प्रति किलो): मैन्था ऑयल 1450, बोल्ड क्रिस्टल (12 नं.)1540, फ्लैक 1478, डीएमओ 1036, टरपीन लैस बोल्ड 1550

मुजफ्फरनगर
चीनी मिल डिली. (क्विं.) (जीएसटी अतिरिक्त): खतौली 3380, बुंदकी 3255, बुढ़ाना 3310, चीनी हाजिर 3550/3700

हापुड़
गुड़-चीनी: चीनी हाजिर 3550/3650, गुड़ (प्रति 40 किलो) बाल्टी 880/890, तिलहन: सरसों (42 प्रतिशत कंडी.) 4250, खल: सरसों 2250/2350, बिनौला 2600/2700, चना छिलका 1950/2000,

जयपुर
अनाज: चावल डीबी 5600/5700, गेहूं (मिल) 2180/2185, मक्की 2070/2075, बाजरा 1840/1850, जौ 1800/1850, ग्वार लूज 3800/3850, ज्वार कैटलफीड 2000/2100, तेल-तिलहन: सरसों(मिल पहुंच) 4550/4575,

श्रीगंगानगर
गेहूं (ढेरी) 2000/2050, ग्वार 3850/3900, जौ 2030/2050,

जोधपुर
गेहूं 2000/2100, जौ 1750/1800, पोपकोन मक्की 4400/4500, ग्वार डिलीवरी (ऑलपेड) 4000/4050, ग्वारगम 7400/7450, बाजरा (गुजरात) 1900/1950, बाजरा (जयपुर) 1900/1920, चना 4000/4100, काबली चना 4800/6000, मूंग 5900/6000,

खन्ना
जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विं.): राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्याइंट)127, राइसब्रान (अखाद्य) 124, खल सरसों 2080, डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद 1250, लाल 1250, कंटीन्यूअस 1300,

लुधियाना
दाल-दलहन: राजमां चित्रा 7500/8000, अरहर दाल 7900/8400, उड़द साबुत 7000/8000, उड़द धोया 9000/9800, छिलका 9000/10000, दाल मसूर 5500/5800, चनादाल 5400/5600,

अमृतसर
चावल: बासमती (1121 नं.) स्टीम 6300/6400, सेला 5500/5550, शरबती साधारण सेला 3750/3850, शरबती स्टीम 4300/4400,चावल 1509 सेला 5100/5200, धान: शरबती 2100/2150, बासमती 1121 धान 285029500, धान (1509) 2600/2675,

बठिंडा
रुई (प्रति मन): जे-34 पंजाब नई 3920/3950, हरियाणा 3900/3925, राजस्थान 3850/3900, खल (प्रति क्विं.): बिनौला 2300/2400, सरसों खल 2180/2190,

फाजिल्का
गेहूं 2140/2150, सरसों 4300/4360 रुई (प्रति मन): (जे-34) 3950/4000,कपास देशी 4900/5000, कपास नरमा (क्विं.) 5050/5125, बिनौला (टैक्सपेड): खल 2600/2700,

जालंधर
गेहूं दड़ा 2130/2140, चावल परमल कच्चा 2450/2500, से ला 2375/2400, मक्की यूपी 2175/2200, बिहार 2325/2335, दाल उड़द छिलका 8600/10200, चना देशी 5150/5250, दाल चना 5300/5400, काबली चना 5000/6000, राजमां चित्रा पुणे 7000/8600, चीन 7400/8000,

करनाल
गेहूं दड़ा 2140/2150, बासमती चावल 6500/6600, धान 1121 नं. 2800/2900, पूसा 1509 धान 2500/2650, शरबती धान 2050/2100, सेला (1509 नं.) चावल 5100/5200, स्टीम 6200/6300,

हिसार
ग्वार 3800/3850, सरसों 4100/4150, गेहूं 2140/2145, नरमा कपास 4900/5000

जींद
जीएसटी अतिरिक्त: गेहूं 2100/2150, आटा (प्रति 44 किलो) 1070/1090, मैदा 1175/1190, देशी घी (एक ली/जार) 370/470, रिफाइंड (टीन) 1385/1400,

भिवानी
जीएसटी अतिरिक्त: सरसों 4050/4100, खल बिनौला मोटी 2250/2500, बिनौला 2700/3200, सरसों तेल 8700/8750, गेहूं 2125/2175, ग्वार 3800/3850, बाजरा 1800/1900 *एनएनएस*

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 247

नियमों के बिना दुनिया

अमेरिका में राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के अधीन मौजूदा सत्ता प्रतिष्ठान विश्व व्यापार व्यवस्था को कमजोर करने के मामले में अब तक के सबसे कट्टर प्रतिष्ठानों में से एक साबित हुआ है। खासतौर पर विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की अपील संस्था के मामले में। अगर डब्ल्यूटीओ का कोई सदस्य दूसरे सदस्य के व्यापारिक नियमों के उल्लंघन के मामले में अपील करता है तो उसकी सुनवाई सात न्यायाधीशों द्वारा की जानी चाहिए। परंतु अमेरिका ने इस अदालत में नई नियुक्तियों को बाधित किया हुआ है। यह प्रक्रिया ट्रंप के कार्यकाल से पहले की है लेकिन उनके कार्यकाल में इसे बढ़ावा मिला है। इस महीने शायद अदालत की कार्यवाही न हो सके क्योंकि पर्याप्त लोग मौजूद नहीं हैं। अंतिम तीन न्यायाधीशों में से दो सेवानिवृत्त होने वाले हैं और एक न्यायाधीश मामलों की सुनवाई नहीं कर सकता। इसका असर वैश्विक स्तर पर होगा। सन 1995 से अपील संस्था बड़ी परियोजनाओं पर केंद्रित रही है। यह सुनिश्चित करने के लिए विश्व व्यापार ऐसी अवस्था को न पहुंच जाए जहां अमेरिका और चीन जैसे बड़े देश अपनी मर्जी से नियम निर्माण पर न सहमत हों और छोटे देश अनुपालन करने को मजबूर न हो जाएं। ऐसे देश द्विपक्षीय व्यापारिक विवादों में जीत हासिल नहीं कर पाएंगे लेकिन उनके पास डब्ल्यूटीओ में आगे की राह निकालने का अवसर रहेगा। यही कारण है कि ट्रंप इस व्यवस्था की अवज्ञा कर रहे हैं।

भारत जैसा छोटा कारोबारी देश जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के बावजूद विश्व व्यापार में केवल दो फीसदी का हिस्सेदार है, उसके लिए उपरोक्त स्थिति किसी त्रासदी से कम नहीं होगी। भारत पहले ही अमेरिका के साथ एक कारोबारी विवाद में उलझा हुआ है। चीन भले ही नियम नहीं तोड़ रहा है लेकिन तमाम अन्य विकासशील देशों की तरह भारत को भी चीन के गैर बाजार आर्थिक झुकाव से अनेक शिकायतें हैं। भारत को भी कुछ आरोप साझा करना होगा, लेकिन उसने डब्ल्यूटीओ में चीन को पर्याप्त ढंग से नहीं रोका। बल्कि उसने चीन को लेकर जो व्यापारिक गतिरोध खड़े किए वे अमेरिका समेत अन्य देशों के साथ उसके विवाद की वजह बन गए। डब्ल्यूटीओ में गए मामलों को लेकर भारत की विधिक तैयारी भी कभी उच्चस्तरीय नहीं रही। यह भी सही है कि डब्ल्यूटीओ सुधार भी काफी समय से लंबित है। बहरहाल, जब तक ट्रंप की जगह कोई ऐसा व्यक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं बनता जो कारोबारों के हित में हो तब तक अपील संस्था में सुधार की संभावना कम ही है। भारत को भी ऐसे वक्त की तैयारी रखनी होगी जहां नियम कायदे नहीं होंगे। इस व्यवस्था में भारत का नया पृथकतावाद विधिक कार्रवाई के बजाय प्रतिकार को उकसावा देगा।

ऐसे हालात में भारत का बहुपक्षीय या द्विपक्षीय नियमों से मुंह मोड़ना खासा संदेहास्पद है। उदाहरण के लिए उपरोक्त संदर्भ में भारत का क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसेप) में शामिल नहीं होने का निर्णय अदूरदर्शी नजर आता है। यदि भारत चीन द्वारा व्यापार को विसंगतिपूर्ण करने को लेकर चिंतित होता तो कम से कम आरसेप विवादों को हल करने की एक व्यवस्था तो उसे मुहैया कराता जो शायद डब्ल्यूटीओ में लंबे समय तक उपलब्ध नहीं रह पाएगी। भारत को अब सक्रियता दिखाते हुए ऐसे अन्य उपाय अपनाने होंगे जिनकी मदद से वह व्यापार नीति के मसले पर वह अपनी आजादी सुनिश्चित कर पाए। परंतु इसे व्यापारिक मामलों में अंतर्मुखी होने के बचाव के तौर पर नहीं अपनाया जा सकता। भारत को अपने हित में अन्य उपाय तलाश करने होंगे, बजाय कि अपनी नीतियों में ऐसे बदलाव करने के जो देश की कंपनियों और कामगारों को ही नुकसान पहुंचाएं।

अजय मोहंती

महज परिधान नहीं एक चरित्र है वर्दी

पुलिसबल में तैनात कर्मचारियों की जरूरतों पर निर्णय-निर्माताओं को सावधानी से विचार करना चाहिए। अनुशासन की अहमियत और शिकायतों के प्रति रवैये पर रोशनी डाल रहे हैं **प्रेमवीर दास**

हाल के महीनों में ऐसी तीन घटनाएं हुई हैं जिन्होंने वर्दी के सवाल को केंद्र में ला खड़ा किया। इनमें से एक मौका कानून व्यवस्था बनाए रखने से जुड़ी दो एजेंसियों के बीच हुए अशोभनीय टकराव का है। इस विवाद के बाद दिल्ली पुलिस के सैकड़ों कर्मचारी अपने मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करने जा पहुंचे और उन्हें शांत कराने के इरादे से पहुंचे अपने ही आयुक्त से सवाल-जवाब करने लगे। हाल ही में हमने राज्यसभा के सभापति के दोनों तरफ खड़े मार्शल को थलसेना के जनरल से मिलती-जुलती वेशभूषा में खड़े हुए देखा। हालांकि इस पर सवाल उठने के बाद मार्शलों की वर्दी फिर से पुराने रूप में लाई जा चुकी है। अभी हाल ही में हमने यह भी देखा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस किस तरह लाठियां लेकर दौड़ा रही है। ये सारी घटनाएं वर्दी-पोशाक के सही मायने पर कुछ अहम सवाल खड़ी करती हैं।

भारत में तीन तरह की वर्दीधारी बल हैं- सेना, अर्द्धसैनिक बल और पुलिस। इनमें से हरेक बल की अपनी खासियत एवं स्पष्ट रूप से परिभाषित जिम्मेदारियां हैं। सेना की बुनियादी जिम्मेदारी देश की क्षेत्रीय अखंडता को सुरक्षित रखना है जबकि अर्द्धसैनिक बल को सुरक्षा की दूसरी पंक्ति के तौर पर काम करने के साथ ही आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा संभालना होता है। वहीं पुलिसबल का काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है। साफ है कि सेना का आम लोगों से सीधा ताल्लुक सबसे कम होता है जबकि पुलिस का सबसे ज्यादा संपर्क होता है। इससे इन बलों पर पड़ने वाला दबाव भी तय होता है और उसमें पुलिस सबसे आगे होती है। लेकिन इन सभी बलों के दायित्वों के निर्वहन में एक बात समान है। भले ही व्यक्तिगत स्तर पर शिकायतें उठाई जा सकती हैं और हमेशा उन्हें सुना भी जाएगा, लेकिन सामूहिक विरोध प्रदर्शन तो अस्वीकार्य है।

भारत के आजाद होने के ऐन पहले 1946 में नौसेना का विद्रोह हुआ था जिसमें सैकड़ों नौसैनिकों ने अपनी बैरकों की घेराबंदी कर अपने अधिकारियों को कुछ समय के लिए बंधक बना लिया था। लेकिन बगावत का झंडा उठाने वाले नौसैनिकों पर जल्द ही काबू पा लिया गया और कई विद्रोहियों को या तो बर्खास्त कर दिया गया या फिर उनके खिलाफ अदालतों में मुकदमे चलाए गए। फिर 1968 में भी नौसेना की टोपास शाखा के नौसैनिकों ने सामूहिक प्रदर्शन किया। इस शाखा के नाविकों का काम जहाजों पर बने शौचालयों की सफाई करना था। ब्रिटिश काल में नौसेना की सभी शाखाओं के नौसैनिक यह काम समान रूप से करते थे। हमारे अधिकारियों अपने काम पर चले गए और रात का खाना भी खाया। बाद में इस घटना की जांचों से पता चला कि नौसैनिकों के बीच ऐसी धारणा पैठ कर गई थी कि उस जहाज के नए कप्तान अनुशासन पर कुछ ज्यादा ही जोर दे रहे हैं। इस शांतिपूर्ण विरोध की वजह चाहे जो भी रही हो, उसे नजरअंदाज नहीं किया गया और उकसाने या भड़काने के काम में किसी भी तरह से शामिल रहे सौ से अधिक नौसैनिकों को सेवामुक्त कर दिया गया।

वर्ष 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर पर सैन्य कार्रवाई के बाद सेना के भीतर भी सामूहिक विरोध की एक घटना हुई थी। बिहार (अब झारखंड) के रामगढ़ कैंट में मौजूद रेजिमेंट की एक सैन्य टुकड़ी ने अचानक दिल्ली की तरफ कूच कर दिया था। लेकिन जल्द ही उन्हें रोका गया और वापस बैरकों में लाया गया। इस घटना में कोई हिंसा नहीं हुई थी लेकिन कूच करने वाले अधिकतर सैनिकों को या तो नौकरी से हटा दिया गया या दंडित किया गया। सैन्यबलों में सामूहिक विरोध की ये कुछ उजागर घटनाएं हैं। कुछ और घटनाएं भी रही होंगी जिनके बारे में अधिक पता नहीं है। असली बात यह है कि इन सभी घटनाओं में सैनिकों के सामूहिक विरोध को अस्वीकार्य आचरण माना गया और उसी हिसाब से उनसे निपटा भी गया। इस दौरान विरोध का कारण बनने वाले बिंदुओं को स्वीकार करने के साथ उन्हें सुधारा भी गया।

वर्दीधारियों के विरोध की हालिया घटनाओं को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। अन्य वर्दीधारी बलों की तुलना में आम नागरिकों के साथ करीबी संपर्क के मामले में पुलिस का काम बेहद जटिल एवं दुरुह है। इसके अलावा पुलिस के दायित्व भी एकदम अलग हैं। पुलिस के कुछ कदम अनावश्यक रूप से कठोर लग सकते हैं लेकिन इनसे बचा भी नहीं जा सकता है। भले ही आंदोलन के मुहाने पर खड़े प्रदर्शन को यह लगा कि अगर आजादी के बाद भी नौसेना में वही परंपरा जारी रहती है तो जहाजों पर मौजूद जगह का अधिकतम इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे नौसैनिकों की संख्या भी बढ़ेगी। जब इस आशय का आदेश जारी किया गया तो नौसैनिकों ने सामूहिक रूप से इसकी अवहेलना की। बड़ी संख्या में नौसैनिकों ने शौचालयों की सफाई को कमतर मानते हुए ऐसा करने से मना कर दिया था। उनके व्यापक विरोध को देखते हुए यह आदेश वापस ले लिया गया लेकिन विरोध करने वाले अधिकतर नौसैनिकों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया।

इसके कुछ साल बाद 1973 में भी नौसेना के भीतर सीमित स्तर का एक और सामूहिक विरोध देखा गया। उस समय नौसेना के अग्रणी पोत आईएनएस मैसूर के सारे नौसैनिकों ने खाना खाने से इनकार कर दिया। उस समय आईएनएस मैसूर सफर पर निकला हुआ था और यह साफ नहीं था कि यह सामूहिक विरोध केवल स्थानीय है या इसका अधिक व्यापक रूप है। कमान मुख्यालय की जांच से पता चला कि यह विरोध केवल उसी जहाज तक सीमित है। जहाज के अधिकारियों के अलावा एडमिरल ने भी इस विरोध की वजह पता करने की कोशिश की लेकिन कुछ भी सामने नहीं आया। नौसैनिक अपना विरोध जताने के बाद शांति से अपने-

(लेखक नौसेना की पूर्वी कमान के पूर्व प्रमुख और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के पूर्व सदस्य हैं)

दुनियाभर का बदलता श्रम बाजार आईटी क्षेत्र में कम होते रोजगार

इंसानी पहलू

श्यामल मजूमदार

कई अध्ययनों से पता चला है कि कृत्रिम मेधा की तकनीक अमेरिका में महज कुछ दशक के भीतर मौजूदा रोजगारों में से आधे पर कब्जा कर लेगी। यानी उत्पादन सबंधी पेशों में बहुत बड़ी तादाद में रोजगार समाप्त होंगे

इन्फोसिस के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी मोहनदास पई ने हाल ही में यह कहकर हलचल मचा दी कि देश के सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) उद्योग में 30,000 से 40,000 मझोले कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है। हकीकत तो यह है कि इस उद्योग में आ रही परिपक्वता के बाद ऐसा आम हो जाएगा। पई फिलहाल मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज के चेयरमैन हैं। उनका यह कहना एकदम सही है क्योंकि जो लोग अपने वेतन के हिसाब से काम में उन्नयन नहीं कर रहे हैं उन्हें विकल्प तलाशने होंगे क्योंकि कंपनियों के पास लोगों की छंटनी करने और अपने आप को नए ढंग से समायोजित करने के अलावा विकल्प नहीं हैं।

हमें तकनीकी क्षेत्र की बेरोजगारी के लिए तैयार रहना होगा क्योंकि तकनीकी प्रगति कौशल, वेतन और रोजगार को गहराई से प्रभावित करेगी। उदाहरण के लिए कोडिंग संबंधी रोजगार आने वाले समय में तमाम आईटी कंपनियों में अप्रासंगिक होते जाएंगे। दुर्भाग्य तो यह है कि न तो मानव और न ही संगठन, तकनीक की दुनिया की गति से तालमेल बिठा पा रहे हैं। उदाहरण के लिए हर 18 महीने में कंप्यूटर प्रोसेसर की शक्ति दोगुनी हो जाती है जबकि हर पांच साल में ये 10 गुना तेज हो रहे हैं। तेज और सस्ते कंप्यूटर तथा कहीं अधिक 'समझदार' सॉफ्टवेयर मशीनों को वे क्षमताएं प्रदान कर रहे हैं जो एक वक्त इंसानों के पास होती थी। आवाज को समझना, एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना और तय रुझानों को पहचानना इसका उदाहरण है।

अब जबकि यह उद्योग उच्च मूल्य सेवाएं देने पर केंद्रित हो रहा है तो आईटी कंपनियों का ध्यान भी अब बड़े आकार के बजाय छोटे लेकिन विशेषज्ञता वाले लोगों के समूह पर है। ऐसे लोग जिनके पास अपने-अपने क्षेत्र की विशेषज्ञता हो। आश्चर्य नहीं कि अब तक काम में आ रहे कॉल सेंटरों का स्थान अब सवाल जवाब वाली स्वचालित व्यवस्था ले रही है।

इन्फोसिस के पूर्व प्रबंध निदेशक विशाल सिक्का ने बहुत पहले इस खतरे के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ा खतरा स्वचालन और कृत्रिम मेधा से है जो आसानी से तकनीकी क्षेत्र के रोजगारों का स्थान ले सकती हैं। ऐसे में आगे बने रहने के लिए उन्हें मौजूदा तयशुदा काम के अलावा ग्राहकों के लिए मूल्यवर्धित काम करना होगा। सिक्का ने कहा था कि देश की सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियां अगर समस्या दूर करने वाली और कम लागत पर काम करने वाली कंपनियों के रूप में सीमित रहीं तो उनका बचे रहना मुश्किल होगा।

कई अध्ययनों से पता चला है कि कृत्रिम मेधा की तकनीक अमेरिका में महज कुछ दशक के भीतर मौजूदा रोजगारों में से आधे पर कब्जा कर लेगी। यानी उत्पादन सबंधी पेशों में बहुत बड़ी तादाद में रोजगार समाप्त होंगे।

बॉस्टन कंसल्टिंग समूह का अनुमान है कि अमेरिका में प्रति घंटे एक इंसानी वेल्डर की सेवा लेना रोबोटिक वेल्डर की तुलना में तीन गुना तक महंगा पड़ सकता है। यानी कंपनियां रोजगार तो देंगी लेकिन केवल उनको जिनमें उच्चस्तरीय काम करने का कौशल हो। विश्व आर्थिक मंच ने 2018 में 'रोजगार का भविष्य' शीर्षक से अपनी रिपोर्ट में कहा था कि रिपोर्ट में शामिल 12 उद्योगों के कुल कार्य घंटों में से औसतन 71 फीसदी मनुष्यों द्वारा किए गए जबकि 29 फीसदी मशीन द्वारा। कहा गया कि सन 2022 तक यह औसत 58 फीसदी मनुष्य और 42 फीसदी मशीन में तब्दील हो जाएगा। उदाहरण के लिए सन 2022 तक किसी संस्थान में सूचना और डेटा प्रसंस्करण तथा सूचनाओं के खोज तथा पारेषण का 62 फीसदी काम मशीनों द्वारा किया जाएगा जबकि सन 2018 में यह प्रतिशत महज 46 था।

बहरहाल कई विशेषज्ञ कहते हैं कि ये आशंकाएं गलत हैं क्योंकि तकनीक के उन्नयन के साथ लोग काम के दोहराव से बचेंगे। जब भी तकनीक में अचानक कोई बड़ा परिवर्तन आता है तो ऐसी स्थिति बनती ही है। परंतु यह भी देखा गया है कि तथाकथित नुकसान उठाने वाले नए उद्योग में कहीं न कहीं अपनी जगह बना ही लेते हैं। यह बहस चलती रहेगी लेकिन सीधा तथ्य यह है कि रोजगार चाहने वालों को अपने कौशल उन्नयन पर जम कर काम करना होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि सन 2022 तक वैश्विक श्रम शक्ति के आधे से अधिक को कौशल में भारी सुधार की आवश्यकता होगी। कौशल संपन्न नए स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति की संभावनाएं नया कौशल अपनाने में पीछे रह गए कर्मचारियों से तकरीबन दोगुनी हैं। जरा सोचिए भारत जैसे देशों पर इसका क्या असर होगा जहां एक करोड़ से अधिक लोग हर वर्ष रोजगार बाजार में शामिल होते हैं। विडंबना यह है कि एक ओर जहां देश की कंपनियों का आधा से अधिक शीर्ष प्रबंधन यह मानता है कि पारंपरिक रोजगार समाप्त हो जाएंगे, वहीं उनमें से एक चौथाई से भी कम ऐसे हैं जिन्होंने अपने संस्थानों में रोजगार उन्नयन या उनके स्वरूप में बदलाव के लिए कोई प्रयास किया है। जबकि यह लगभग अनिवार्य हो चुका है।

कानाफूसी

टकराव का परिणाम

मध्य प्रदेश के वन मंत्री उमंग सिंघार और अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन) एपी श्रीवास्तव के बीच छिड़ा शीतयुद्ध विभाग के रोजमर्रा के कामकाज को प्रभावित कर रहा है। बीते एक महीने से अधिक समय में अधिकारियों की मेजों पर फाइलों का अंबार लग गया है। अधिकारियों की पदस्थापना और पदोन्नति से संबंधित फाइलें जस की तस अटकी हुई हैं। यह भी एक कारण है कि भारतीय वन सेवा के तमाम अधिकारी दूसरी जगह पदस्थापना की तलाश में हैं। करीब 16 अधिकारियों ने अन्य विभागों तथा केंद्र में प्रतिनियुक्ति का आवेदन कर दिया है। सिंघार और श्रीवास्तव के बीच के मतभेद उस समय सार्वजनिक हो गए जब मंत्री ने पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुए कथित पौधरोपण घोटाले की जांच आर्थिक अपराध शाखा से कराने की अनुशंसा की थी। श्रीवास्तव इस बात से सहमत नहीं थे जिसके चलते दोनों में टकराव की स्थिति बन गई।

ट्विटर पर तकरार

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पिछले कुछ समय में उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी भाजपा सरकार पर सोशल मीडिया साइट ट्विटर के माध्यम से जमकर हमले किए। इन हमलों से बौखलाई सरकार की ओर से जवाब देने का दायित्व संभाला उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने। उन्होंने यहां तक कह डाला कि यादव और वाड्रा को अपना नाम बदलकर ट्विटर यादव और ट्विटर वाड्रा कर लेना चाहिए क्योंकि दोनों अपने राजनीतिक एजेंडा को आगे बढ़ाने का काम ट्विटर के माध्यम से ही करते हैं।

आपका पक्ष

महिला सुरक्षा पर संसद में चिंता

हाल में घटित सामूहिक दुष्कर्म की घटना ने देश को स्तब्ध कर दिया है जिस वजह से महिला सुरक्षा को लेकर देश भर में आक्रोश है। कई जगहों पर महिलाएं दुष्कर्म के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रही हैं। संसद में भी महिला सुरक्षा पर चिंता जाहिर की गई। संसद सदस्य जया बच्चन ने दुष्कर्मियों को सामूहिक रूप से सजा की मांग करते हुए महिला सुरक्षा के प्रति अपनी चिंता प्रकट की। अन्य सदस्यों ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में शीघ्र सुनवाई कर सामाजिक बदलाव एवं अनुशासन के लिए मौत की सजा दिए जाने की मांग की। जवाब में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन की सहमति से कठोर कानून बनाने की बात कही है। निर्भया कांड के बाद सदन में दुष्कर्म के खिलाफ कानून में सुधार लाकर सख्त किए थे। फिर भी कानून को ताक में रखते हुए अपराधियों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म जैसे अमानवीय कृत्य बिना किसी भय के किए जा रहे हैं। एनसीआरबी

हैदराबाद में सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद पटना में विरोध प्रदर्शन करतीं डॉक्टर

की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2017 में देश में दुष्कर्म के कुल 32,559 मामले दर्ज किए गए हैं। मध्य प्रदेश में दुष्कर्म के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना को 18 से 30 वर्ष की महिलाओं के लिए देश में सबसे असुरक्षित राज्य माना गया है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि उत्तर प्रदेश सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में सबसे आगे है। जब देश में इस तरह के मामले सामने आते हैं तब देशभर की महिलाओं में भय का माहौल देखने को मिलता है। खासकर नौकरीपेशा महिलाएं ऐसी घटनाओं के बाद खुद को काफी असुरक्षित महसूस करती हैं। कई महिलाएं सुनसान सड़कों, कम यात्री वाले सार्वजनिक वाहनों में प्रवेश करने से डरती हैं। कई महिलाओं को अपनी नौकरी छोड़ कर घर में बैठना पड़ता है। सरकार महिला सशक्तीकरण के लिए अपने बजट से प्रति वर्ष वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकार भी महिला सुरक्षा हेतु कदम उठाती है। महिला सुरक्षा एवं सशक्तीकरण का दायित्व सरकार एवं समाज दोनों पर बराबरी का है। इसके लिए सरकार को एवं समाज को जवाबदेही स्वीकार करना चाहिए। सरकार को महिला सुरक्षा हेतु एक सख्त कानून एवं समयबद्ध न्यायिक प्रक्रिया जैसे ठोस कदम उठाने चाहिए जबकि समाज द्वारा अभिभावकों को अपने पुत्रों को अच्छे संस्कार देना चाहिए।

निशांत महेश त्रिपाठी, नागपुर

कानून का पालन कड़ाई से हो

हैदराबाद में सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्याकांड के बाद देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इससे पहले निर्भया कांड से पूरे देश में आक्रोश था। जिसके बाद कठोर कानून बनाने की पहल की गई। इसके बावजूद इस तरह की घटनाओं में कमी नहीं आ रही है। सिर्फ कैंडल मार्च से इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। सिर्फ मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित करना एक मानसिक छलावा करने जैसे होगा। ऐसी घटनाओं से निजात पाने के लिए कानून का कड़ाई से पालन करना होगा। सभी पोर्न साइट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना होगा। सामाजिक रूप से हर माता-पिता का दायित्व बनता है कि वह अपने बच्चों को शिक्षा दे कि महिलाओं का सम्मान करे, उनका शोषण न करे, क्योंकि दुष्कर्म करने वाला कोई भी हो वह आखिरकार हमारे समाज से ही निकल कर आते हैं।

नृपेंद्र अभिषेक, छपरा

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।

कागज आयात कम करने पर जोर : गडकरी

देश में विविध प्रकार के कागज उद्योग की मौजूदगी के बावजूद बड़ी मात्रा में कागज के आयात पर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घरेलू कागज उद्योग को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत बताई। उन्होंने कागज उद्योग में कच्चे माल के तौर पर बांस का इस्तेमाल बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि सरकार ने बांस मिशन के लिए बजट में 1,300 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। गडकरी ने मंगलवार को प्रगति मैदान में तीन दिवसीय कागज उद्योग प्रदर्शनी 'पेपरेक्स-2019' का उद्घाटन करते हुए कहा, 'देश में कागज के विविध क्षेत्रों की मौजूदगी के बावजूद बड़े पैमाने पर आयात हो रहा है। मैं खासतौर से छोटी कागज और पल्प इकाइयों की वृद्धि संभावनाओं को लेकर चिंतित हूं। यह क्षेत्र एमएसएमई का महत्त्वपूर्ण हिस्सा है।' उन्होंने कागज उद्योग में बांस और उसके पल्प के अधिक से अधिक इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बांस का उपयोग बढ़ने से कागज उद्योग और किसान दोनों को फायदा होगा।

सम्मेलन का आयोजन इंडियन एग्रो ऐंड रिसाइकिल्ड पेपर मिल्स एसोसिएशन (आईएआरपीएमए) की इकाई इनपेपर इंटरनैशनल द्वारा किया जा रहा है। कागज की बढ़ती मांग के चलते वर्ष 2025 तक इसकी मांग मौजूदा एक करोड़ 85 लाख टन से बढ़कर ढाई करोड़ टन तक पहुंच जाने का अनुमान है। आईएआरपीएमए के महासचिव पी जी मुकुंदन ने कहा, 'उभरती हुई नई जीवन शैली और पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग विभिन्न प्रकार के कागज के विकास का अवसर प्रदान करते हैं। कागज उद्योग में विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। ग्राहक अब पर्यावरण अनुकूल विकल्प के तौर पर कागज को प्राथमिकता देने लगे हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक के बजाय कागज का इस्तेमाल बढ़ रहा है।' जेके पेपर के प्रबंध निदेशक हर्षपति सिंघानिया ने कहा, 'यूरोप और अमेरिका में कागज की खपत में कमी आ रही है जबकि एशिया और लातिन अमेरिकी देशों में खपत बढ़ रही है। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता कागज का बाजार है।' सिंघानिया ने कहा सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक को कम करने का आग्रह कर रही है। ऐसे में इसकी मांग को पूरा करने के लिए कागज उद्योग को नवीन विकल्प विकसित करने की जरूरत है। भाषा

महाराष्ट्र में चीनी उत्पादन घटा

चीनी मिलों ने ईरान, अफ्रीका को 15 लाख टन निर्यात का किया समझौता

वीरेंद्र सिंह रावत
लखनऊ, 3 दिसंबर

- चीनी उत्पादन 50 फीसदी घटकर 19 लाख टन रहा जो पिछले साल 41 लाख टन था
- महाराष्ट्र में करीब एक महीने की देरी से चीनी मिलों का परिचालन शुरू हुआ जिसके कारण चीनी उत्पादन में गिरावट आई
- चालू सीजन में घरेलू चीनी उत्पादन में अनुमानित कमी की आंशिक वजह एथनॉल उत्पादन में हो रही बढ़ोतरी है

महाराष्ट्र में पिछले दिनों हुई बारिश और चुनाव के कारण पेराई सत्र में देरी की वजह से 30 नवंबर, 2019 तक घरेलू चीनी उत्पादन 50 फीसदी से अधिक घटकर 19 लाख टन रह गया। पिछले वर्ष की इस अवधि में यह करीब 41 लाख टन था।

भारतीय चीनी मिल संघ (इस्मा) के मुताबिक 2019-20 के चालू चीनी सत्र के दौरान केवल 279 चीनी मिलें परिचालन में थीं, जबकि नवंबर 2018 के अंत तक 418 इकाइयों में गन्ना पेराई हो रही थी।

चालू सत्र के दौरान महाराष्ट्र में करीब एक महीने की देरी - नवंबर 2019 के तीसरे हफ्ते से चीनी मिलों का परिचालन शुरू होने के कारण चीनी उत्पादन में गिरावट आई। लिहाजा चीनी के कुल उत्पादन में भारी कमी आई है। अब तक केवल 43 मिलों ने पेराई शुरू की है और राज्य में 67,000 टन चीनी उत्पादन हुआ है, जबकि पिछले वर्ष 175 चीनी मिलें सक्रिय थीं जिनसे 19 लाख टन चीनी उत्पादन हुआ था।

देश के शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में 111 मिलों में गन्ने की पेराई हो रही थी जिनसे करीब 11 लाख टन कुल उत्पादन हुआ, जबकि पिछले सत्र में 105 मिलों में पेराई हुई थी और उत्पादन 10 लाख टन से नीचे रहा।

कर्नाटक में 30 नवंबर तक 61 चीनी मिलों में पेराई हो रही थी जिनसे 5,21,000 टन चीनी उत्पादन हुआ। इस्मा की रिपोर्ट से पता चलता है पिछले वर्ष यहां 63 इकाइयों में कुल 8,40,000 टन चीनी उत्पादन हुआ था।

दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व मॉनसून में हुई अधिक बारिश के कारण गुजरात में भी इस वर्ष चीनी मिलों में पेराई करीब तीन हफ्तों की देरी से शुरू हुई। अब तक 14 मिलों में पेराई हुई जिनसे 75,000 टन चीनी उत्पादन हुआ, जबकि पिछले पेराई सत्र में 16 मिलों में पेराई हुई थी जिनसे 2,05,000 टन उत्पादन हुआ था।

इस बीच दूसरे राज्यों में पेराई शुरू हो चुकी है और इसकी रफ्तार में धीरे-धीरे तेजी आ रही है। दूसरे राज्यों में करीब 50 मिलें सक्रिय थीं जिनसे अब तक उत्पादन 1,41,000 टन के स्तर पर पहुंच गया। करीब 60 मिलों ने 2,21,000 टन चीनी उत्पादन किया है।

कारोबार और बाजार सूत्रों का हवाला देते हुए इस्मा ने बताया कि करीब 15 लाख टन चीनी निर्यात के लिए समझौते हो चुके हैं जिसमें मिलों द्वारा बंदरगाह पर स्थित रिफाइनरों के साथ समझौते भी शामिल हैं। भारतीय चीनी के बड़े निर्यात गंतव्य में ईरान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और अफ्रीकी देश आदि शामिल हैं।

उत्तर भारत के राज्यों में पिछले कुछ महीनों से चीनी की कीमतें (एक्स मिल) 3,250-3,300 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर पर बनी हुई हैं, जबकि पश्चिम और दक्षिण भारत के राज्यों में यह 3,100-3,250 रुपये प्रति क्विंटल के निचले स्तर पर है।

चालू सत्र में उत्तर प्रदेश में 1.2 करोड़ टन चीनी उत्पादन का अनुमान है जो 2019-20 में देश के अनुमानित उत्पादन का करीब 45 फीसदी है। इस्मा की पिछले रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू चीनी उत्पादन 20 फीसदी घटकर 2.6 करोड़ टन रह सकता है, जबकि 2018-19 में 3.3 करोड़ टन उत्पादन हुआ था। इस साल गन्ने का रकबा 48.3 लाख हेक्टेयर आंका गया है।

चालू सीजन में घरेलू चीनी उत्पादन में अनुमानित कमी की आंशिक वजह एथनॉल उत्पादन में हो रही बढ़ोतरी है जिससे घरेलू स्तर पर गन्ने की कुछ पैदावार का इस्तेमाल ईंधन में मिलाने के लिए भी किया जाएगा।

नवंबर में स्वर्ण आयात 5 महीने के शीर्ष स्तर पर

रॉयटर्स
नई दिल्ली/मुंबई, 3 दिसंबर

- दामों में गिरावट के बाद जौहरियों ने खरीद में किया इजाफा
- नवंबर में आयात बढ़कर हुआ 71 टन, अक्टूबर में था 40 टन
- प्रीमियम बढ़ोतरी ने रिफाइनरों को किया कच्चे सोने का आयात बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित

नवंबर में देश का स्वर्ण आयात पिछले महीने की तुलना में 78 प्रतिशत उछलकर पांच महीने के शीर्ष स्तर पर पहुंच गया क्योंकि दुनिया में सोने के इस दूसरे सबसे बड़े बाजार में जौहरियों ने दाम गिरने के बाद फिर से इसका स्टॉक करना शुरू कर दिया है। सरकार के एक सूत्र ने आज यह जानकारी दी।

भारत द्वारा अधिक आयात किए जाने से वैश्विक दामों को मदद मिलने की संभावना है जो वर्ष 2019 में अब तक 12 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ चुके हैं, लेकिन इससे देश का व्यापार घाटा और रुपये पर दबाव भी बढ़ सकता है। भारत सोने की अपनी लगभग संपूर्ण मांग को आयात के जरिये ही पूरा करता है। पहचान उजागर न करने की शर्त पर सूत्र ने बताया कि नवंबर में भारत ने 71 टन सोने का आयात किया है, जबकि अक्टूबर में 40 टन आयात किया गया था। हालांकि नवंबर 2018 की तुलना में आयात 16 प्रतिशत कम रहा है। मुंबई के सराफा कारोबारी रिद्धि-सिद्धि के निदेशक मुकेश कोठारी ने कहा कि दीवाली के बाद सोने के दामों में सुधार हुआ है जिससे जौहरियों को स्टॉक भरने का मौका मिला है। देशवासियों ने अक्टूबर में धनतेरस और दीवाली पर्व मनाए थे। तब सोने की खुदरा मांग शीर्ष स्तर पर थी क्योंकि इसे शुभ और समृद्धि बढ़ाने वाला माना जाता है। सितंबर में 39,885 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर जाने के बाद नवंबर में स्थानीय सोने का वायदा भाव गिरकर 37,477 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था।

सूत्र ने कहा कि मूल्य के हिसाब से नवंबर में कुल आयात 2.94 अरब डॉलर रहा है जो पिछले साल के 2.76 अरब डॉलर की तुलना में कुछ ज्यादा है। स्वर्ण आयातक बैंक के मुंबई स्थित एक सराफा कारोबारी ने कहा कि जौहरियों की मांग बढ़ने से भारत में पिछले महीने के आधिकारिक घरेलू दामों की तुलना में सोने ने साढ़े पांच महीने में पहली बार प्रीमियम पर कारोबार करना शुरू कर दिया है जिसने रिफाइनरों को कच्चे सोने का आयात बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है।

उन्होंने कहा कि भारी छूट की वजह से रिफाइनरों के लिए अक्टूबर तक आयात आकर्षक नहीं था। चूंकि सोने ने प्रीमियम पर कारोबार करना शुरू कर दिया है इसलिए उन्होंने आयात में इजाफा किया है।

नवंबर में आधिकारिक घरेलू दामों पर कारोबारियों ने प्रति औंस 1.5 डॉलर तक का प्रीमियम वसूला है, जबकि अक्टूबर में प्रति औंस 21 डॉलर तक की छूट दी गई थी। घरेलू दामों में 12.5 प्रतिशत का आयात शुल्क और तीन प्रतिशत का बिक्री कर शामिल रहता है। सरकारी अधिकारी ने बताया कि नवंबर के दौरान देश के स्वर्ण आयात में कच्चे सोने की हिस्सेदारी 33 टन रही है, जबकि अक्टूबर में 8.5 टन आयात किया गया था। मुंबई के एक कारोबारी ने कहा कि दिसंबर में देश का स्वर्ण आयात गिरकर 40 टन से नीचे जा सकता है जो पिछले साल 73 टन था।

अंतरराष्ट्रीय और घरेलू भाव

As on Dec 3	International Price	International %Chg#	Domestic Price	Domestic %Chg#
METALS ($/tonne)				
Aluminium	1,789.5	4.4	1,883.1	-3.3
Copper	5,855.5	5.8	6,207.3	1.2
Nickel	13,625.0	-24.0	14,367.4	-20.0
Lead	1,912.0	-4.2	2,120.2	5.1
Tin	16,500.0	-0.3	17,296.7	2.2
Zinc	2,285.5	3.4	2,580.6	2.6
Gold ($/ounce)	1,469.0*	-5.1	1,653.5	-1.2
Silver ($/ounce)	17.0*	-11.8	19.3	-6.4
ENERGY				
Crude Oil ($/bbl)	60.6*	3.7	61.8	8.2
Natural Gas ($/mmBtu)	2.4*	2.1	2.4	1.3
AGRI COMMODITIES ($/tonne)				
Wheat	186.3	18.2	299.3	5.7
Maize	184.2*	4.1	314.1	5.3
Sugar	343.6*	12.9	482.9	-0.5
Palm oil	652.5	23.1	1,040.9	21.5
Rubber	1,555.5*	2.7	1,822.1	-5.8
Coffee Robusta	1,396.0*	8.9	1,876.1	-9.8
Cotton	1,407.7	9.5	1,563.1	-1.2

* As on Dec 03, 19 1800 hrs IST, # Change Over 3 Months, Conversion rate 1 USD = 71.7& 1 Ounce = 31.1032316 grams.

Notes:
1) International metals, Indian basket crude, Malaysia Palm oil, Wheat LIFFE and Coffee Karnataka robusta pertains to previous days price. 2) International metal are LME Spot prices and domestic metal are Mumbai local spot prices except for Steel. 3) International Crude oil is Brent crude and Domestic Crude oil is Indian basket. 4) International Natural gas is Nymex near month future & domestic natural gas is MCX near month futures. 5) International Wheat, White sugar & Coffee Robusta are LIFF E future prices of near month contract. 6) International Maize is MATIF near month future, Rubber is Tokyo-TOCOM near month future and Palm oil is Malaysia FOB spot price. 7) Domestic Wheat & Maize are NCDEX future prices of near month contract, Palm oil & Rubber are NCDEX spot prices. 8) Domestic Coffee is Karnataka robusta and Sugar is M30 Mumbai local spot price. 9) International cotton is Cotton no.2-NYBOT near month future & domestic cotton is MCX Future prices near month tures.

Bloomberg chartMaker — Compiled by BS Research Bureau

एमसीएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	19.0	11850
Oil and Oilseeds	225.1	66831
Spices	0.6	13
Metal(Dec 02)		
Metal- non ferrous	5405.7	65139
Metal- precious	8016.9	420
Oil and gas(Dec 02)		
Gas	2904.1	45164
Oil	16336.0	2010

एनसीडीईएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	89.3	110096
Grains	197.1	101795
Oil and Oilseeds	645.5	490775
Others	123.2	68045
Pulses	152.2	65625
Spices	78.7	30531

एमसीएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Aluminium Mini (Dec 31)	134.6	0.8
Aluminium (Dec 31)	134.6	0.8
Crude Oil (Dec 18)	4008.0	0.7
Crude Oil Mumbai (Dec 18)	4009.0	0.7
Natural Gas (Dec 26)	168.0	0.5
Nickel (Dec 31)	1009.9	0.4
Losers (* % Change)		
Zinc (Dec 31)	182.2	-1.5
Zinc Mini (Dec 31)	182.6	-1.4
Cardamom (Dec 13)	2834.4	-1.2
Mentha Oil (Dec 31)	1300.9	-1.1
Lead Mini (Dec 31)	152.4	-0.8
Lead (Dec 31)	152.4	-0.8

एनसीडीईएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Moong-Mertacity (Dec 20)	6600.0	1.5
Mustard Seed Rape Oil (Dec 20)	4367.0	0.4
Ref Soy Oil-IDR-2016 (Dec 20)	823.8	0.4
Chana-Bikaner (Dec 20)	4459.0	0.3
Losers (* % Change)		
Jeera Unjha (Dec 20)	16115.0	-1.1
GuarGum 5T-Jodhpur (Dec 20)	7235.0	-1.1
CastorSeed New-Disa (Dec 20)	3982.0	-1.1
Coriander-Kota (Dec 20)	6538.0	-1.1
Turmeric Nizamabad (Dec 20)	5642.0	-0.8
Barley Jaipur (Apr 20)	1691.5	-0.6
Shankar Kapas-Rajkot (Apr 30)	1066.0	-0.6
Guar Seed 10 (Dec 20)	4030.0	-0.4

एमसीएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Kapas Surendranagar (Feb 28)	1043.0	4.6
Cotton-Rajkot (Dec 31)	19050.0	2.1
Gold Petal-Mumbai (Dec 31)	3866.0	1.1
Silver Micro-Ahemd (Feb 28)	44760.0	0.7
Discount over spot price (In %)		
Menthol Oil Chandaus (Dec 31)	1300.9	-7.2
Aluminium Mum (Dec 31)	134.6	-6.3
Alumini-Mumbai (Dec 31)	134.6	-6.3
Copper Mum (Dec 31)	432.1	-3.1
Nickel Mumbai (Dec 31)	1009.9	-2.0
Lead Mum (Dec 31)	152.4	-1.7
Lead Min Mumbai (Dec 31)	152.4	-1.7
Zinc Mumbai (Dec 31)	182.2	-1.5

एनसीडीईएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Paddy-Basmati-Karnal (Dec 20)	3164.0	2.1
Barley Jaipur (Dec 20)	2131.5	0.5
Soy Bean Indore (Dec 20)	4102.0	0.3
Maize-Sangli (Dec 20)	1971.0	0.2
29 mm Cotton-Rajkot (Dec 20)	18560.0	0.2
Discount over spot price (In %)		
Coriander-Kota (Dec 20)	6538.0	-5.5
Turmeric Nizamabad (Dec 20)	5642.0	-4.5
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (Dec 20)	7235.0	-2.3
Jeera Unjha (Dec 20)	16115.0	-1.8
Moong-Merta City (Dec 20)	6600.0	-1.8
Crude Palm Oil Kandl (Dec 31)	683.2	0.0

कल का हाजिर भाव

औद्योगिक

Metals	..............Mumbai
Aluminium utensil scrap /kg	98........(98)
Aluminium ingots /kg	135........(135)
Brass sheet cutting /kg	314........(314)
Brass utensil scraps/kg	295........(294)
Copper heavy scrap /kg	413........(413)
Copper utensil scraps/kg	389........(389)
Copper wire bar /kg	445........(446)
Lead ingots /kg	152........(152)
Nickel Cathodes /kg	1030........(1040)
Tin slabs /kg	1240........(1240)
Zinc slabs /kg	185........(188)

Source:Bombay Metal Exchange

Cotton	..............Mumbai
Bengal Deshi /Qtl	10714........(10714)
DCH - 32 /Qtl	11360........(11360)
Jaydhar /Qtl	10011........(10011)
Shankar- 6 /Qtl	11220........(11220)

Source:Cotton Association of India

Oil	..............Mumbai
Castor FSG /10kg	863........(855)
Castor Comm /10kg	853........(845)
Ricebran oil/10kg	760........(760)
Groundnut oil /10kg	1020........(1020)
Linseed oil /10kg	845........(845)
Karanji /10kg	760........(760)
Palm oil /10kg	762........(760)
Sunflower exp ref /10kg	830........(830)
Sunflower oil exp /10kg	790........(790)
Soyabean ref / 10kg	810........(800)

Source:Bombay Commodity Exchange

सॉफ्ट

Sugar	..............Mumbai
Mumbai M-30 /Qtl	3352-3572 ....(3360-3572)

Source:Bombay Sugar Merchants Association

ऊर्जा

Crude Brent-$/Barrel	....
NYSE Crude	56.38........(55.96)
Brent Crude (UK)	60.81 ....(60.77)
Brent Crude (WTI)	55.96........(55.96)
NYSE Natural Gas-$/Mmbtu	2.39 ....(2.33)
Furnace/ 180 Cst &/bbl	226.44 ....(223.58)
Naptha spot /Rs/MT	45170........(45170)
LSHS spot/ M.T.	36150........(36150)
Furnace Oil spot/ K.L.	33950........(33950)

Source:Petroleum Bazaar.com

सर्राफा

Gold	..............Mumbai
Standard (99.50 Purity) /10 gms	38111........(37827)
Pure (99.90 Purity) /10 gms	38265........(37979)
Silver.999/ kg	44560........(44200)

Source:India Bullion & Jewellers Association

@SPOT PRICE(MCX, NCDEX & ICEX)

Commodity	Unit	PClose	Price (₹.) Close
29 mm Cotton-Rajkot (N)	1 B	18509.10	18529.80
Alumini-Mumbai (M)	1 K	140.15	143.60
Bajra-Delhi (N)	1 Q	1950.00	1895.00
Barley Jaipur (N)	1 Q	2125.25	2121.75
Brass-Jamnagar (M)	1 K	300.00	299.50
Cardamom-Vand. (I)	1 K	2882.00	2925.00
Castor Seed Disa (N)	1 Q	4007.00	4036.65
Castor Seed-Kadi (N)	X	4190.00	3975.00
Chana Bikaner (N)	1 Q	4312.75	4337.20
Chana Delhi (N)	1 Q	4479.55	4522.50
Chana-Akola (N)	X	4375.00	4550.00
Coriander-Gondal (N)	X	6617.00	6600.00
Coriander-Jaipur (N)	X	6875.00	6833.35
Coriander-Kota (N)	1 Q	6937.15	6916.25
Cotton Seed Oilck Ak (N)	1 Q	1996.85	2009.60
Cotton Seed Oilck Ka (N)	1 Q	1932.30	1925.00
Cotton-Kadi (N)	1 B	18462.30	18453.30
CPO-Kandla (M)	10 K	680.60	683.00
Crude Palm Oil Kandl (N)	10 K	680.20	683.25
Diamond 0.3 - Surat (I)	1 CT	881.85	882.00
Diamond 0.5-Surat (I)	1 CT	1541.80	1539.75
Diamond 1-Surat (I)	1 CT	3472.20	3471.75
Gold Ahm (M)	10 G	37795.00	38062.00
Gold Guinea-Ahmedaba (M)	8 G	30358.00	30572.00
Gold Petal-Mumbai (M)	1 G	3794.00	3825.00
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (N)	X	7400.00	7407.30
Guar Seed 10 MT-Jodh (N)	1 Q	3999.10	4001.25
Guarseed-Jodhpur (I)	1 Q	4000.00	3925.00
Gur Muzaffar Nagar (N)	40 K	1017.85	1017.85
Isabgulseed-Unjha (I)	1 K	93.25	93.70
Jeera Jodhpur-Jodhpu (N)	X	17100.00	17000.00
Jeera Unjha (N)	1 Q	16455.25	16409.50
Kapas Kadi-Kadi (N)	X	998.40	1002.55
Kapas-Rajkot (N)	X	991.00	991.60
Lead Mum (M)	1 K	155.25	155.00
Maize Kharif-Nizamab (N)	X	1897.50	1905.00
Maize Rabi-Gulabbagh (N)	1	2245.15	2242.35
Maize-Erode (N)	X	2066.65	2100.00
Maize-Feed/Ind-Delhi (N)	1 Q	2110.00	2120.00
Maize-Sangli (N)	X	1965.00	1967.10
Moong-Merta City (N)	1 Q	6622.50	6719.45
Mustardseed Alwar (N)	20 K	4514.25	4540.00
Nickel Mumbai (M)	1 K	1037.10	1030.40
Paddy-Basmati-Karnal (N)	X	3100.00	3100.00
Paddy-Basmati-Karnal (I)	1 Q	3140.00	3153.00
Pepper-Ernakulam (I)	1 K	349.40	350.00
Pepper-Kochi (N)	1 Q	34850.00	35125.00
Rape mustards-Patan (I)	20 K	782.00	785.00
Rapeseed Must.Seed (N)	X	2095.25	2100.85
RBD Palm Olein Kakin (N)	10 K	744.00	746.25
Ref Soya Oil Indore (N)	10 K	815.25	821.70
Ref Soya Oil Mum (N)	10 K	803.15	805.85
Ref Soya Oil Nagpur (N)	10 K	815.00	824.50
Rubber-Kochi (N)	1 Q	13100.00	13062.50
Rubber-Kochi/Ernak. (I)	1 Q	13100.00	13050.00
Silver M-Ahemdabad (M)	1 K	44132.00	44437.00
Soy Bean Indore (N)	1 Q	4070.00	4091.00
Soy Bean Kota (N)	1 Q	3989.50	4007.50
Soy Bean Nagpur (N)	1 Q	4040.00	4070.30
Soy Bean-Akola (N)	X	4070.00	4275.00
Soymeal Indore (N)	1 T	33500.00	33700.00
Soyoil-Indore (I)	10 K	808.10	822.50
Steel Long-Ghaziabad (I)	1 T	27930.00	28000.00
Steel Long-MGG (I)	1 T	29010.00	29100.00
Steel Long-Raipur (I)	1 T	26010.00	26060.00
Sugar M Delhi (N)	1 Q	3295.00	3285.00
Sugar M Grade-Kanpur (N)	1 Q	3390.30	3364.60
Sugar M Grade-Kolhap (N)	1 Q	3271.65	3282.50
Sugar M Kolkatta (N)	1 Q	3457.15	3447.60
Sugar M Muzaff (N)	1 Q	3305.65	3301.10
Sugar S-Kolhapur (N)	1 Q	3123.75	3134.15
Turmeric Nizamabad (N)	1 Q	5938.65	5907.15
Wheat Delhi (N)	1 Q	2252.50	2258.75
Wheat Kota (N)	1 Q	2140.00	2131.40
Wheat New Indore (N)	1 Q	2192.50	2200.00
Wheat New Kanpur (N)	1 Q	2073.75	2073.75
Wheat New-Rajkot (N)	1 Q	2195.00	2200.00
Yellow Peas Mum (N)	1 Q	4655.40	4650.00
Zinc Mumbai (M)	1 K	187.25	185.00

* as on Dec 02, 19

(M) MCX ,(N) NCDEX & (I) ICEX Spot prices

जिंस वायदा

DAY SESSION

दिवस सत्र (मंगलवार)

कृषि जिंस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Dec 31	19070, 19110, 19020, 19050	1539	229	9056
Jan 31	19230, 19250, 19200, 19220	94	17	2134
CottonSeed Oil-Akola NCDEX(1 Q)				
Dec 20	1930, 1948, 1914, 1927	16440	1289	39160
Jan 20	1951, 1971, 1936, 1947	20280	1604	45120
Feb 20	1968, 1989, 1956, 1967	3280	306	19700
Mar 20	1995, 2011, 1989, 1997	330	33	2260
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1072, 1073, 1066.5, 1068.5	124	31	596
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1071, 1072.5, 1065, 1066	506	250	3856
Grains				
Barley Jaipur NCDEX(1 Q)				
Apr 20	1690, 1700.5, 1690, 1691.5	230	5	420
May 20	1700, 1700, 1700, 1700	200	7	410
Guar Seed 10 NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	4042, 4076, 4018, 4030	21565	2318	38535
Jan 20	4078, 4094, 4036, 4050	26345	2799	59130
Feb 20	4112, 4128, 4074, 4082	390	47	1000
Oil and Oilseeds				
CastorSeed New-Disa NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	4030, 4040, 3974, 3982	7395	789	31260
Jan 20	4070, 4084, 4012, 4020	5255	731	22060
Feb 20	4032, 4032, 4020, 4020	35	5	3755
Apr 20	4050, 4050, 4050, 4050	10	2	10
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Dec 31	682.8, 685.2, 679.5, 683.3	18410	1149	50960
Jan 31	682.7, 685.3, 679.3, 682.6	7840	556	14950
Feb 28	685.1, 690, 684.5, 685.6	480	41	620
Mentha Oil MCX(1 K)				
Dec 31	1319.4, 1320, 1298.1, 1300.9	311.4	719	283.32
Jan 31	1323.8, 1328, 1309, 1310.9	15.12	38	17.28
Mustard Seed Rape Oil NCDEX(1 Q)				
Dec 20	4359, 4370, 4343, 4367	8290	622	25580
Jan 20	4390, 4409, 4379, 4404	6450	542	6820
Feb 20	4391, 4391, 4391, 4391	10	1	110
Apr 20	4266, 4266, 4266, 4266	10	1	1120
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Dec 20	821, 827.6, 821, 823.8	9435	1102	27045
Jan 20	823.6, 831.6, 823.4, 827.6	13985	1251	46435
Feb 20	821.6, 829, 821.6, 824.8	3420	133	10815
Mar 20	823, 823, 823, 823	5	1	30
Soyabean Indore NCDEX(1 Q)				
Dec 20	4110, 4138, 4086, 4102	23310	2986	56880
Jan 20	4148, 4172, 4116, 4134	31305	3671	146930
Feb 20	4170, 4192, 4138, 4156	16210	1434	85135
Mar 20	4194, 4218, 4164, 4180	3525	545	23755
Apr 20	4216, 4216, 4204, 4204	10	2	185
Others				
GuarGum 5T-Jodhpur NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	7280, 7370, 7206, 7235	7475	1010	18115
Jan 20	7399, 7472, 7306, 7339	9045	1263	49435
Feb 20	7505, 7565, 7410, 7511	230	28	445
Pulses				
Chana-Bikaner NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	4450, 4492, 4436, 4459	15960	1274	28590
Jan 20	4467, 4515, 4455, 4480	17580	1310	34420
Mar 20	4428, 4434, 4405, 4413	350	30	2240
Apr 20	4335, 4380, 4335, 4355	120	11	300
Moong-Mertacity NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	6600, 6600, 6600, 6600	25	1	25
Spices				
Cardamom MCX(1 K)				
Dec 13	2850, 2860, 2815.1, 2834.4	0.7	7	2.9
Jan 15	2800, 2820, 2765, 2797.4	1.3	13	8.4
Feb 14	2653.8, 2653.8, 2653.8, 2653.8	0.1	1	1.4
Coriander-Kota NCDEX(1 Q)				
Dec 20	6648, 6655, 6456, 6538	2090	185	7110
Jan 20	6570, 6622, 6466, 6520	1790	159	5350
Apr 20	6990, 6990, 6835, 6903	300	30	2460
Jeera Unjha NCDEX(1 Q)				
Dec 20	16300, 16340, 16065, 16115	1227	278	1884
Jan 20	16200, 16320, 15915, 15935	852	262	1512
Mar 20	15850, 15850, 15840, 15840	21	7	210
Turmeric Nizamabad NCDEX(1 Q)				
Dec 20	5662, 5680, 5612, 5642	1280	220	8340
Mar 20	6082, 6082, 5946, 5988	1355	235	2290
Apr 20	6062, 6062, 5982, 6024	340	68	1370

धातु

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Metal- non ferrous				
Aluminium MCX(1 K)				
Dec 31	134.5, 134.9, 134.1, 134.75	3985	580	10185
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Dec 31	134.5, 134.9, 134.05, 134.7	1652	1426	3316
Jan 31	135.2, 135.7, 135.15, 135.6	141	104	273
Copper MCX(1 K)				
Dec 31	432.4, 432.6, 429.3, 430.05	13572.5	4592	17252.5
Jan 31	437.3, 437.45, 434.45, 434.8	262.5	102	777.5
Lead MCX(1 K)				
Dec 31	152.4, 152.45, 151.6, 152.25	8345	1330	8235
Lead Mini MCX(1 K)				
Dec 31	152.5, 152.6, 151.7, 152.3	3663	3017	3583
Jan 31	152.7, 152.7, 152.05, 152.45	84	78	80
Nickel MCX(1 K)				
Dec 31	1012.4, 1013.8, 1004.2, 1005.6	8500.5	5019	2932.5
Jan 31	1009.5, 1010, 1002.6, 1004.3	76.5	49	160.5
Zinc MCX(1 K)				
Dec 31	182.8, 182.8, 181.3, 181.75	25015	4009	22135

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Zinc Mini MCX(1 K)				
Dec 31	183, 183, 181.75, 182.2	8032	6115	7079
Jan 31	183.5, 183.5, 182.1, 182.45	299	228	543
Feb 28	183.05, 183.5, 183, 183.2	3	3	2
Metal- precious				
Gold MCX(10 G)				
Dec 05	37930, 38250, 37880, 38075	0.04	24	0.1
Feb 05	37881, 38162, 37825, 38107	7.12	6022	17.57
Apr 03	37902, 38200, 37855, 38172	0.1	95	1.77
Gold Guinea MCX(8 G)				
Dec 31	30534, 30610, 30480, 30599	0	168	0
Jan 31	30485, 30575, 30485, 30532	0	3	0
Gold Mini MCX(10 G)				
Dec 05	37874, 38220, 37840, 38156	0.01	39	0.06
Jan 03	37949, 38183, 37879, 38127	0.77	6397	0.89
Feb 05	37910, 38169, 37843, 38113	0.13	1160	0.14
Gold Petal MCX(1 Gm)				
Dec 31	3860, 3876, 3859, 3873	0	659	0.01
Jan 31	3857, 3864, 3831, 3862	0	143	0
Silver MCX(1 K)				
Dec 05	44250, 44685, 44150, 44563	3.93	37	10.41
Mar 05	44684, 45042, 44590, 44969	275.43	7358	333.75
May 05	45263, 45533, 45263, 45394	0.18	6	1.92
Silver Micro MCX(1 K)				
Feb 28	44740, 45049, 44621, 44984	23.03	15078	26.36
Apr 30	45240, 45539, 45123, 45466	0.81	658	0.83
Silver Mini MCX(1 K)				
Feb 28	44823, 45050, 44620, 44987	72.62	11713	48.18
Apr 30	45205, 45546, 45132, 45487	0.63	118	0.77

तेल एवं गैस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Gas				
Natural Gas MCX(1 MB)				
Dec 26	169, 172.4, 168.4, 171.7	56751mb	27150	37499mb
Jan 28	168.5, 171.3, 167.8, 170.8	3828mb	2050	8778mb
Feb 25	164.3, 166.5, 163.9, 166.3	395mb	286	1458mb
Oil				
Crude Oil MCX(1 BL)				
Dec 18	4025, 4042, 4012, 4019	8614bl	42969	2786bl
Jan 17	4036, 4054, 4020, 4027	124bl	959	145bl
Crude Oil Mumbai MCX(1 Bl)				
Dec 18	4020, 4042, 4012, 4019	1706bl	64792	601bl

सायं सत्र (सोमवार)

कृषि जिंस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Dec 31	19150, 19210, 19060, 19120	2976	477	8912
Jan 31	19320, 19370, 19240, 19290	429	73	2113
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1071, 1074, 1070, 1072	40	10	580
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1071, 1077, 1069.5, 1072	488	325	3861
Oil and Oilseeds				
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Dec 31	676, 686.6, 672.9, 684.6	17180	1192	51720
Jan 31	675, 686.7, 674.4, 684.7	4130	342	11030
Feb 28	678, 690.1, 677.5, 688.3	490	46	420
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Dec 20	813, 824.2, 810.2, 822.8	15115	1423	30620
Jan 20	818, 828.8, 814.6, 826.6	17665	1433	44235
Feb 20	816.2, 827, 816.2, 823.4	2800	237	7850

धातु

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Metal- non ferrous				
Aluminium MCX(1 K)				
Dec 31	133.7, 134.75, 133.1, 134.6	13920	1976	10145
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Dec 31	133.55, 134.7, 133.1, 134.6	4869	3738	3175
Jan 31	134.7, 135.65, 134.1, 135.5	309	218	217
Copper MCX(1 K)				
Dec 31	433.5, 435, 431.45, 432.1	29817.5	9677	13917.5
Jan 31	439.25, 439.9, 436.5, 437.15	455	178	715
Feb 28	440.4, 441.9, 440.4, 441.15	5	2	-
Lead MCX(1 K)				
Dec 31	153.7, 153.95, 152.2, 152.35	21935	3526	6950
Lead Mini MCX(1 K)				
Dec 31	153.7, 153.95, 152.3, 152.4	8997	7145	3036
Jan 31	154, 154.1, 152.55, 152.7	152	140	62
Nickel MCX(1 K)				
Dec 31	1010.3, 1015.7, 998.3, 1009.9	20907	12358	1995
Jan 31	1007, 1012.2, 995.7, 1007.8	328.5	218	145.5
Zinc MCX(1 K)				
Dec 31	185.6, 185.6, 181.95, 182.2	48475	7860	18535
Zinc Mini MCX(1 K)				
Dec 31	185.15, 185.55, 182.35, 182.6	17536	13129	5806
Jan 31	185.7, 185.7, 182.75, 182.95	548	496	438
Feb 28	185, 185, 182.5, 184	5	5	2
Metal- precious				
Gold MCX(10 G)				
Dec 05	37717, 38028, 37100, 37952	0.48	356	0.12
Feb 05	37928, 37984, 37770, 37949	11.43	9707	16.65
Apr 03	37873, 37990, 37829, 37964	0.27	229	1.7
Gold Guinea MCX(8 G)				
Dec 31	30530, 30575, 30439, 30551	0	307	0
Jan 31	30500, 30525, 30470, 30513	0	18	0
Gold Mini MCX(10 G)				
Dec 05	38240, 38240, 37715, 37915	0.09	193	0.07
Jan 03	37951, 38020, 37827, 37987	1.24	10443	0.8
Feb 05	37905, 37985, 37792, 37964	0.22	1797	0.13
Gold Petal MCX(1 Gm)				
Dec 31	3871, 3871, 3859, 3866	0	1118	0.01
Jan 31	3851, 3860, 3850, 3857	0	238	0
Silver MCX(1 K)				
Dec 05	44290, 44416, 44077, 44344	10.62	273	12.09
Mar 05	44949, 44949, 44549, 44730	427.2	11551	318.48
May 05	45383, 45554, 45101, 45244	3.81	124	1.8
Silver Micro MCX(1 K)				
Feb 28	44963, 44963, 44580, 44760	47.56	29855	23.91
Apr 30	45411, 45411, 45119, 45250	1.23	1039	0.72
Aug 31	47000, 47000, 47000, 47000	0	1	0
Silver Mini MCX(1 K)				
Feb 28	44945, 44945, 44557, 44751	138.27	22044	42.6
Apr 30	45414, 45414, 45119, 45263	1.21	230	0.58

तेल एवं गैस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Gas				
Natural Gas MCX(1 MB)				
Dec 26	169.2, 170.6, 164.7, 168	159849mb	72092	34736mb
Jan 28	167.5, 169.7, 164.5, 167.4	11746mb	5881	8955mb
Feb 25	164.2, 165.4, 161, 163.5	1500mb	979	1473mb
Oil				
Crude Oil MCX(1 BL)				
Dec 18	4000, 4067, 3990, 4008	33076bl	153396	1528bl
Jan 17	4039, 4077, 4001, 4019	564bl	4338	128bl
Crude Oil Mumbai MCX(1 Bl)				
Dec 18	3971, 4066, 3971, 4009	6904bl	247249	354bl

g-grams, k-kilograms, q-quintals, t-tonnes, b-bales,bl-barels,mb-mmBTU,m-Mnd; Quantity & Open interest in tonnes except for crude oil and natural gas; For Gas is '000 mmBTU & for crudeoil in '000 barrel; Market price in ₹.

चेन्नई के षणमुग ने खोजा इसरो के चंद्रयान-2 का विक्रम लैंडर

नासा ने की पुष्टि, मुख्य क्रैश साइट से एक किलोमीटर के दायरे में फैला है मलबा

गिरीश बाबू

चेन्नई के 33 वर्षीय षणमुग सुब्रमण्यन के ट्विटर खाते पर 1,824 ट्वीट हैं और उनके फॉलोअर की संख्या 5,690 है। उनकी प्रोफाइल में लिखा है कि वह मैकेनिकल इंजीनियर, ब्लॉगर, ऐप डेवलपर, क्यूए इंजीनियर और माइक्रोसॉफ्ट एजर डेवलपर हैं। इसके साथ ही उनके प्रोफाइल में एक पहचान और जुड़ी है, 'मैंने विक्रम लैंडर को खोजा!'

सुब्रमण्यन ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा प्रक्षेपित किए गए चंद्रयान-2 के विक्रम लैंडर के अवशेषों को खोजकर अहम उपलब्धि हासिल की है। चंद्रयान-2 के लैंडर विक्रम को 7 सितंबर को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी लेकिन अंतिम समय में उसका नियंत्रण टूट गया और वह चांद की सतह पर क्रैश हो गया।

इसरो के साथ साथ अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भी विक्रम की खोज कर रही थी लेकिन षणमुग ने नासा द्वारा जारी की गई तस्वीरों के जरिये चांद की सतह पर विक्रम के अवशेषों को पहली बार खोज निकाला।

तस्वीर में विक्रम लैंडर के चांद की सतह से टकराने वाले स्थान और संबंधित अवशेष वाले क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं। नासा ने इसकी घोषणा करते हुए कहा, 'लूनर रिकॉनसन्स ऑर्बिटर टीम (एलआरओसी) ने 17 सितंबर को ली गई तस्वीरें 26 सितंबर को जारी की थीं और बहुत से लोगों ने विक्रम को खोजने के लिए इन्हें डाउनलोड किया था। षणमुग ने सही तथ्यों के साथ एलआरओ टीम से संपर्क किया। इसके बाद एलआरओ टीम ने सभी तस्वीरों का दोबारा विश्लेषण किया और इसे सही पाया।'

नासा ने कहा कि षणमुग सुब्रमण्यन ने एलआरओ परियोजना टीम से संपर्क किया और मुख्य दुर्घटनास्थल से लगभग 750 मीटर उत्तर पश्चिम में पहले टुकड़े की पहचान की। मदुरै (तमिलनाडु) के रहने वाले षणमुग पहले प्रमुख आईटी कंपनी कॉग्निजेंट में काम करते थे और फिलहाल लेनॉक्स इंडिया टेक्नोलॉजी सेंटर के साथ जुड़े हैं। उन्होंने इसरो के चंद्रयान-2 अभियान को टेलीविजन पर देखा और जब उन्हें खबर मिली कि नासा भी लैंडर को नहीं खोज पाया तो उन्होंने इसे एक चुनौती के रूप में लिया। लैंडर के उतरने वाले स्थान की जानकारी, लैंडर की आखिरी स्थिति और चयनित जगह से इसकी दूरी की जानकारी लेने के बाद उन्होंने नासा द्वारा जारी तस्वीरों के संबंधित हिस्से का गहन विश्लेषण किया।

षणमुग ने एक टेलीविजन साक्षात्कार में बताया कि इसके लिए उन्होंने करीब चार दिन 7-8 घंटे रोजाना समय दिया। उन्होंने 3 अक्टूबर को अपने ट्विटर खाते पर दो तस्वीरों की तुलना करते हुए लैंडिंग स्थल से करीब एक किलोमीटर दूर एक स्थान को चिह्नित करते हुए पूछा कि क्या यह विक्रम लैंडर है और क्या लैंडर चंद्रमा की सतह में दफन हो गया है? उन्होंने इसके सत्यापन के लिए एलआरओ टीम के वैज्ञानिकों को भी एक ई-मेल भेजा। षणमुग ने 17 नवंबर को एक अन्य साइट को चिह्नित करते हुए लिखा कि यह लैंडर का दुर्घटना स्थल हो सकता है। उन्होंने इस तस्वीर की तुलना जुलाई 2019 की उसी स्थल की एक तस्वीर से की और दिखाया कि दोनों में थोड़ा अंतर दिख रहा है।

नासा ने मलबे की खोज की घोषणा करने के साथ ही षणमुग को श्रेय दिया और उन्हें एक ईमेल भेजा कि उनकी खोज ने एलआरओसी टीम को अतिरिक्त खोज करने तथा प्राथमिक टक्कर स्थल के साथ-साथ इसके आसपास बिखरे अन्य अवशेषों को भी खोजने में मदद की। नासा ने विक्रम के मलबे वाली तस्वीरों में षणमुग की खोज को भी दिखाया है। अंतरिक्ष एजेंसी ने यह सुनिश्चित किया कि अंतिम परिणामों की घोषणा करने से पहले सभी हितधारकों को अवसर मिले।

षणमुग लेनॉक्स इंडिया में टेक्निकल आर्किटेक्ट हैं और उन्होंने भारतीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रकाशनों द्वारा रिव्यू की गई वेबसाइट तथा ऐंड्रॉइड ऐप विकसित किए हैं। उनके नवोन्मेष में विशेष रूप से टेक्स्ट के लिए बनाया गया वेब ब्राउजर है जो डेटा की खपत कम करता है, ब्रेल आवाज को सपोर्ट करता है और फोन या ऐप की मदद से लेख पढ़ता है। उन्होंने बहुत से ट्वीट एक साथ डिलीट करने वाला ऐप और प्रशांत महासागर तथा हिंद महासागर क्षेत्र में सुनामी अलर्ट वाले ऐप विकसित किए। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा सेंट जोसफ मैट्रिक हायर सेकंडरी स्कूल, मदुरै और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तिरुनेलवेल्ली से मैकेनेकिल इंजीनियरिंग में बीई की शिक्षा ग्रहण की।

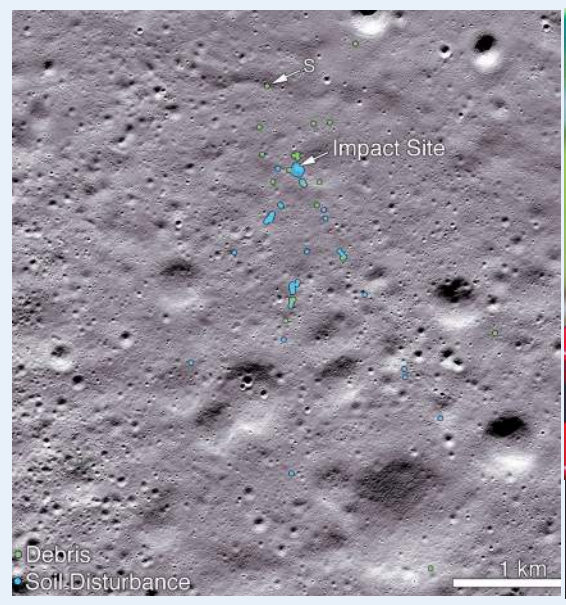

षणमुग सुब्रमण्यन
टेक्निकल आर्किटेक्ट, लेनॉक्स इंडिया

बुलेट ट्रेन के सहारे केंद्र पर दबाव

सुशील मिश्र

महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के साथ ही बुलेट ट्रेन परियोजना पर संकट के बदल मंडराने लगे हैं। इस परियोजना की समीक्षा के आदेश भी दिए जा चुके हैं। परियोजना की लागत में महाराष्ट्र सरकार को करीब 5,000 करोड़ रुपये देने हैं। हालांकि नई सरकार इस परियोजना पर रोक नहीं लगाना चाह रही है लेकिन इसके निर्माण में पूंजी लगाने के पक्ष में नहीं है। राज्य की वित्तीय हालत का हवाला देकर महाराष्ट्र सरकार परियोजना का पूरा खर्च केंद्र सरकार पर थोपने की रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है।

शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस गठबंधन महाविकास आघाडी के नेताओं का कहना है कि हम किसी परियोजना के विरोध में नहीं है लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता किसान हैं। गठबंधन के दबाव में ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के समीक्षा का आदेश दिया है। वह कहते हैं कि हमने बुलेट ट्रेन परियोजना पर रोक नहीं लगाई बल्कि समीक्षा के आदेश दिये हैं। मुख्यमंत्री की बात को आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र सरकार के मंत्री जयंत पाटिल ने कहा कि राज्य सरकार यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि राज्य पर 4 लाख 71 हजार करोड़ रुपये के कर्ज को देखते हुए क्या बुलेट ट्रेन जैसी परियोजनाओं को टाला जा सकता है।

पाटिल ने कहा कि हमलोग इस बात की समीक्षा कर रहे हैं कि राज्य के विकास के लिए कौन सी परियोजना महत्त्वपूर्ण है और क्या बुलेट ट्रेन जैसी परियोजनाओं को बाद के चरण के लिए रखा जा सकता है। इस परियोजना की व्यवहार्यता तथा राज्य सरकार को इसके लिए कितने पैसे चुकाने होंगे इस पर विचार करने के लिए सरकार ने एक बैठक बुलाई है। बुलेट ट्रेन परियोजना को किसानों और आदिवासियों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा है क्योंकि उसके लिए उनकी भूमि का अधिग्रहण होना है।

सरकार के सूत्रों की मानी जाए तो यह सरकार बुलेट ट्रेन का विरोध नहीं करेगी लेकिन हम इसकी लागत में राज्य से एक भी पैसा नहीं देने वाले हैं। शिवसेना के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि यह केंद्र सरकार की परियोजना है इसलिए इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार दे, महाराष्ट्र से इससे कोई खास फायदा नहीं है, गुजरात का इससे फायदा है इसीलिए इस परियोजना को केंद्र और गुजरात सरकार मिलकर पूरा करें। महाविकास गठबंधन के नेताओं की होने वाली बैठक में इस बात पर चर्चा हुई है, कि जो पैसा बुलेट ट्रेन परियोजना में दिया जाना है उसको किसानों को दिया जाना चाहिए, केन्द्र सरकार पर दबाव बनाया जाए और जनता के बीच यह बताने की कोशिश की जाए कि वह किसानों के लिए काम कर रही है। ऐसे में केंद्र सरकार को मजबूर होकर पूरा पैसा देना होगा क्योंकि अब यह परियोजना बंद करना संभव नहीं होगा।

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की कुल लागत 1.08 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है जिसमें महाराष्ट्र को 5,000 करोड़ रुपये खर्च करने है। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन बनाया जा रहा है यह जमीन राज्य सरकार की संस्था एमएमआरडीए की है उस समय एमएमआरडीए ने इस जमीन की कीमत 3,500 करोड़ रुपये महाराष्ट्र सरकार से मांगी थी लेकिन तब भाजपा की सरकार थी जिससे संस्था की बात विकास के नाम पर दब गई, अब राज्य सरकार यह पैसा भी केंद्र सरकार से देने की मांग करेगी। महाराष्ट्र में करीब 350 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है जिसमें से अभी तक महज 35 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण हो सकी है। राज्य सरकार के सहयोग के बिना यह संभव नहीं है। इसी के बल पर महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है।

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ड्रीम परियोजना मानी जाती है। सितंबर 2017 में प्रधानमंत्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने बुलेट ट्रेन परियोजना की आधारशिला रखी थी। इस परियोजना के लिए जापान ने 0.1 फीसदी की ब्याज पर 88,000 करोड़ रुपये का कर्ज दिया है। इस परियोजना को 2013 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और अभी तक करीब 45 फीसदी जमीन का अधिग्रहण भी हो चुका है।

संकट के बादल

- परियोजना की लागत में महाराष्ट्र सरकार को देने हैं करीब 5,000 करोड़ रुपये
- राज्य की वित्तीय हालत का हवाला देकर महाराष्ट्र सरकार परियोजना का पूरा खर्च केंद्र पर थोपने की रणनीति तैयार करने में जुटी
- मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की कुल लागत आंकी गई है 1.08 लाख करोड़ रुपये
- बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बनाया जा रहा है बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन

... आर्थिक सुस्ती ने तोड़ा घर का सपना

पृष्ठ 1 का शेष

रियल एस्टेट एनालिस्ट फर्म एनारॉक के अनुमानों के मुताबिक नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अधबने 142,500 फ्लैटों का काम 2013 में शुरू किया गया था। उनकी कुल कीमत करीब 800 अरब रुपये है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इसी इलाके में सबसे अधिक अधबने फ्लैट हैं। मुंबई में सबसे अधिक 154,000 अधबने फ्लैट हैं जिनकी कीमत 2 लाख करोड़ रुपये है।

आंकड़ों के मुताबिक 2015 से दिल्ली-एनसीआर में जितने की फ्लैट लॉन्च किए गए उनमें से आधे यानी करीब 100,000 फ्लैट नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में हैं। आर्थिक सुस्ती ने उन हजारों लोगों का सपना तोड़ दिया जिन्होंने फ्लैट बुक कराए थे। आम्रपाली और जेपी ग्रुप जैसे बड़े बिल्डरों और आरजी ग्रुप जैसे छोटे डेवलपरों के 30 हजार से अधिक खरीदारों को चपत लगी है।

रियल एस्टेट में सुस्ती से स्थानीय कारोबारी, वेंडर, प्रॉपर्टी डीलर, ट्रांसपोर्टर और सप्लायर भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। पान की दुकान चलाने वाले मनोज कुमार का कहना है कि 2014 से उनका कारोबार कम से कम 60 फीसदी घट गया है। इन दिनों उनका गुजारा गौड़ सिटी शॉपिंग मॉल में जाने वाले ग्राहकों से होता है। उनकी पत्नी और परिवार मॉल के बाहर परांठे और सब्जी बेचते हैं। स्थानीय ट्रक एसोसिएशन के राधेश्याम तिवारी के मुताबिक कभी यहां रोजाना 100 से अधिक ट्रक चलते थे। लेकिन अब यह संख्या दो दर्जन रह गई है। यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि इस इलाके में कितने लोगों का रोजगार छिना है लेकिन सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस के अनुराग कुमार ने कहा कि यह संख्या एक लाख से ऊपर हो सकती है। मोटे अनुमान के मुताबिक 2015 से दस लाख से अधिक कार्यदिवसों का नुकसान हुआ है। रियल एस्टेट में सुस्ती की शुरुआत वर्ष 2010 के शुरुआत में हुई थी लेकिन इसे थामने के उपाय नहीं होने से स्थिति गहरा गई। क्रेडाई वेस्टर्न यूपी के अध्यक्ष निर्वाचित और एबीए कॉरपोरेशन के निदेशक अमित मोदी के मुताबिक 2010 की शुरुआत में रियल एस्टेट गतिविधियों में तेजी आई थी लेकिन सरकार बाजार का रुख भांपने में नाकाम रही और उसने इसके लिए जरूरी कदम नहीं उठाए। उन्होंने कहा, 'शुरुआती दिनों में किसानों के मुआवजे का मुद्दा उठा था और इससे बहुत नुकसान हुआ। इसके बाद डेवलपरों को दर्जनों नियामकीय मंजूरियां लेनी पड़ी जबकि वे इस उद्देश्य के लिए सरकार से जमीन खरीद चुके थे। इससे उनकी लागत बढ़ गई। इससे उनके फ्लैट की कीमत अव्यावहारिक हो गई।'

वर्ष 2010 में जब रियल एस्टेट की कीमतों में अचानक तेजी आई तो कई डेवलपर इसमें कूद पड़े। इनमें से कई डेवलपरों को ज्यादा अनुभव भी नहीं था। बेहद प्रतिस्पर्द्धी बाजार में कई डेवलपरों ने प्रोजेक्ट की वास्तविक लागत से कम पर फ्लैट की पेशकश की। इससे स्थिति और बदतर हो गई। मोदी ने कहा, 'कई प्रॉपर्टी डीलर और दूसरे क्षेत्रों से जुड़े लोग भी रियल एस्टेट में कूद गए और उन्होंने खरीदारों को आकर्षित करने के लिए बेहद कम कीमत पर फ्लैट की पेशकश की। ऐसे प्रोजेक्टों को नाकाम होना ही था क्योंकि उनकी निर्माण लागत भी नहीं निकल पाई।' नरेडको के अध्यक्ष निरंजन हीरानंदानी ने रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए विशेष कोष बनाने के सरकार के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा, 'यह अच्छी पहल है लेकिन इस क्षेत्र के लिए ज्यादा बुनियादी समाधान की जरूरत है। इसे पटरी पर लाने के लिए बकाया ऋण के एकमुश्त पुनर्गठन की जरूरत है।'कीमतों में कमी से मदद मिल रही है। नरेडको और एनारॉक के मुताबिक सितंबर, 2019 की तिमाही में ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में जनवरी-मार्च, 2015 की तुलना में अनबिके फ्लैटों की संख्या में 46 फीसदी की गिरावट आई। इसकी वजह यह रही कि बिक्री की तुलना में नए प्रोजेक्ट बहुत कम रहे। इसके बावजूद ग्रेटर नोएडा में 37 महीने की बिक्री के बराबर अनबिके फ्लैट हैं। सितंबर 2019 तक इस इलाके में करीब 50 हजार अनबिके फ्लैट थे जिनमें से अधिकांश ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हैं।

- रियल एस्टेट में सुस्ती की शुरुआत वर्ष 2010 के शुरुआत में हुई थी लेकिन इसे थामने के उपाय नहीं होने से स्थिति गहरा गई
- मोटे अनुमान के मुताबिक 2015 के बाद से दस लाख से अधिक कार्यदिवसों का नुकसान हुआ है

अगले वर्ष से होगी एक्सएलआरआई के एनसीआर परिसर की शुरुआत

अभिषेक रक्षित

जैवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट (एक्सएलआरआई) अगले वर्ष से नई दिल्ली-एनसीआर स्थित अपने कैंपस में शैक्षणिक सत्र की शुरुआत करने जा रहा है। पहले चरण में संस्थान के बिजनेस प्रबंधन कार्यक्रम के लिए दो सेक्शन के लिए 60-60 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा।

संस्थान का नया परिसर गुरुग्राम से 25 किलोमीटर दूर झज्जर जिले के नौरंगपुर में स्थित है। यह 36.34 एकड़ भूमि में फैला है और पहले चरण में 240 छात्रों के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे को पूरा करने पर काम कर रहा है। एक्सएलआरआई एआईसीटीई प्रमाणन के लिए आवेदन करेगा जबकि नए परिसर को स्वर्ण-स्तर का हरित भवन प्रमाणन मिल गया है।

दिल्ली-एनसीआर कैंपस में भी एक्सएलआरआई-जमशेदपुर की तरह ही शिक्षण व्यवस्था एवं पाठ्यक्रम के होने की उम्मीद है और मुख्य संस्थान के प्राध्यापक भी यहां आकर कक्षाएं लेंगे। जैवियर प्रवेश परीक्षा देने वाले छात्र एक्सएलआरआई के दिल्ली-एनसीआर परिसर में प्रवेश ले सकेंगे। इसके लिए उन्हें ज़ैट-2020 प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करते समय इसका चुनाव करना होगा।

झज्जर के नौरंगपुर में 36.34 एकड़ भूमि पर फैला है परिसर

एक्सएलआरआई के निदेशक पी क्रिस्टी ने कहा, 'आगामी भविष्य में भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और इसके लिए बिजनेस क्षेत्र में अधिक नेतृत्वकर्ताओं की जरूरत होगी। एक्सएलआरआई ने देश में अपने विस्तार का फैसला लिया है और भारत के उत्तरी, पश्चिमी तथा दक्षिण हिस्सों में नए कैंपस स्थापित कर रहे हैं।'

साथ ही जैवियर प्रवेश परीक्षा 2020 के पंजीकरण की तिथि को बढ़ाकर 10 दिसंबर कर दिया गया है और इस वर्ष के लिए पंजीकरण में देरी पर लगने वाले शुल्क को भी हटा लिया गया है। इस साल जनवरी में जमशेदपुर में 70 साल का सफर पूरा करने के बाद एक्सएलआरआई ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में अपने नए परिसर की आधारशिला रखी। यह परिसर 50 एकड़ में फैला है, और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थापित किया जा रहा है। यहां करीब 5,000 छात्रों को पढ़ाने की सुविधा होगी जहां प्रबंधन क्षेत्र में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इस वर्ष अक्टूबर माह में संस्थान ने 361 छात्रों के बैच में शत-प्रतिशत समर इंटर्नशिप प्लेसमेंट का लक्ष्य हासिल किया और इस पूरी प्रक्रिया में 86 कंपनियां शामिल थीं। इस वर्ष समर इंटर्नशिप के लिए औसत वेतन में 12.15 प्रतिशत इजाफा हुआ और यह वर्ष 2018 के 1.07 लाख रुपये महीना से बढ़कर 1.2 लाख रुपये पर पहुंच गया। इस बार बीएफएसआई क्षेत्र ने सबसे अधिक वेतन दिया जो 2.5 लाख रुपये महीना था।

संस्थान में पहली बार आने वाली कंपनियां जैसे बेन ऐंड कंपनी, एमेजॉन, एनआईआईएफ, फोनपे, उड़ान, शेल, ओला, अदाणी, रूपेक, कोर्नफेरी आदि ने भी छात्रों को नौकरी प्रस्ताव दिए। सलाहकार क्षेत्र की कंपनियों ने 16 प्रतिशत छात्रों को नौकरियां दीं तो वहीं बीएफएसआई क्षेत्र ने 40 प्रतिशत छात्रों को। 17 प्रतिशत नौकरी प्रस्ताव बिजनेस प्रबंधन क्षेत्र के छात्रों को दिए गए। दूसरे क्षेत्रों में एनालिटिक्स, उत्पाद प्रबंधन, बिजनेस डेवलपमेंट, ब्रांड मैनेजमेंट और स्ट्रेटजी शामिल रहे।

आईएसबी में नौकरी प्रस्ताव 15 फीसदी बढ़े

विनय उमरजी

इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी) में प्लेसमेंट प्रक्रिया के पहले दिन नौकरी प्रस्तावों में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। आईएसबी के प्रबंधन में परास्नातक कार्यक्रम (पीजीपी) के लिए चल रहे प्लेसमेंट पर अंतरिम प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, पहले दिन 1,383 छात्रों को नौकरी प्रस्ताव दिए गए जबकि पिछले वर्ष पहले दिन 1,194 छात्रों को नौकरी प्रस्ताव दिए गए थे। संस्थान में प्लेसमेंट की प्रक्रिया जारी है और इस बार के बैच से 85 प्रतिशत छात्रों का प्लेसमेंट हो चुका है।

इस वर्ष आईएसबी के विद्यार्थियों को मिले नौकरी प्रस्तावों की औसत सैलरी (सीटीसी) 26.15 लाख रुपये सालाना रही। पीजीपी छात्रों को यहां आने से पहले दो वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक का कार्य अनुभव होता है और आईएसबी से पहले और बाद के उनके वेतन में 124 फीसदी का अंतर दर्ज किया गया। दूसरे शब्दों में, आईएसबी आने के बाद अंतिम प्लेसमेंट प्रक्रिया के दौरान छात्रों को यहां आने से पहले मिलने वाले वेतन से 124 प्रतिशत अधिक वेतन मिला। इस बार 231 कंपनियां आईएसबी कैंपस में नौकरी के लिए आ रही हैं जिसमें से 65 कंपनियां पहली बार संस्थान में आ रही हैं।

आईएसबी के डीन राजेंद्र श्रीवास्तव कहते हैं, 'आईएसबी की स्थापना भारत एवं दुनिया के लिए भविष्य के नेतृत्वकर्ता तैयार करने के दृष्टिकोण के साथ की गई थी। 890 छात्रों के साथ भारत में परास्नातक स्तर पर संबंधित क्षेत्र में सबसे अधिक छात्रों के समूह के साथ आईएसबी पीजीपी स्तर पर उच्च गुणवत्ता एवं कौशल युक्त छात्र समूह प्रदान करता है।'

सलाहकार फर्म कुल नौकरी प्रस्तावों में 22.75 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे हैं। इसके बाद आईटी क्षेत्र (14.93 प्रतिशत), ई-कॉमर्स (11.30 प्रतिशत) और बीएफएसआई (11.23 प्रतिशत) क्षेत्र का स्थान है। कार्य के आधार पर देखें तो भी कंसल्टिंग 23.79 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे है। इसके बाद बिक्री एवं विपणन (15.40 प्रतिशत), उत्पाद प्रबंधन (15.04 प्रतिशत), प्रबंधन/रणनीतिक प्लानिंग (13.09 प्रतिशत) और परिचालन (7.52 प्रतिशत) हैं। कंसल्टिंग के शीर्ष नियोक्ताओं में एक्सेंचर, अल्वारेज ऐंड मार्शल, एटी कियर्नी, बेन ऐंड कंपनी, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, डालबर्ग, डेलॉइट इंडिया, डेलॉइट यूएसआई, ईऐंडवाई, ईवाई पार्थेनन, जीईपी, केपीएमजी, मैकिंजी ऐंड कंपनी, पीडब्लूसी डीआईएसी, पीडब्लूसी इंडिया, रोलैंड बर्जर, सीमेंस मैनेजमेंट कंसल्टिंग और जेडएस एसोसिएट्स कंपनियां थीं जिन्होंने 314 छात्रों को नौकरी प्रस्ताव दिए। आईटी, ई-कॉमर्स और तकनीक क्षेत्र में एडीपी, एमेजॉन, ब्लैकबक, बाजयू, इलेक्ट्रॉनिक्स आर्ट्स, फ्लिपकार्ट, गूगल, इनमोबी, मीडिया डॉट नेट सॉफ्टवेयर सर्विसेज, एमफिन, माइक्रोसॉफ्ट, मिंत्रा, नागारो सॉफ्टवेयर, नायका, ओला, फोनपे, रेजरपे, थॉटवर्क्स, उड़ान, उबर, वीएमवेयर और जोमैटो मुख्य रहीं।